

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग

सामान्य अध्ययन

VOLUME-5
भारतीय अर्थव्यवस्था
कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार,
जनसंख्या एवं नगरीकरण
अध्यायवार सॉल्ड पेपर्स

प्रधान सम्पादक
आनन्द कुमार महाजन
सम्पादन एवं संकलन
यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स PCS परीक्षा विशेषज्ञ समिति

कम्प्यूटर ग्राफिक्स
बालकृष्ण, चरन सिंह
सम्पादकीय कार्यालय
यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स
12, चर्च लेन, प्रयागराज-211002

 मो. : 9415650134
Email : yctap12@gmail.com
website : www.yctbooks.com

प्रकाशन घोषणा

प्रधान सम्पादक एवं प्रकाशक आनन्द कुमार महाजन ने ओम साई ऑफसेट, प्रयागराज से मुद्रित करवाकर,
यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स, 12, चर्च लेन, प्रयागराज-211002 के लिए प्रकाशित किया।

इस पुस्तक को प्रकाशित करने में सम्पादक एवं प्रकाशक द्वारा पूर्ण सावधानी बरती गई है।
फिर भी किसी त्रुटि के लिए आपका सुझाव एवं सहयोग सादर अपेक्षित है।

किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र प्रयागराज होगा।

मूल्य : 295/-

विषय-सूची

भारतीय अर्थव्यवस्था

■ भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ.....	7-8
■ आर्थिक विकास एवं नियोजन	9-16
■ राष्ट्रीय आय.....	17-20
■ कृषि क्षेत्र	21-24
■ उद्योग क्षेत्र	25-35
■ सेवा क्षेत्र.....	36-37
■ भारतीय वित्तीय प्रणाली : मुद्रा बाजार एवं पूँजी बाजार	38-60
■ बीमा क्षेत्र.....	61-62
■ लोक वित्त (बजट एवं कराधान).....	62-76
■ वैदेशिक क्षेत्र	77-87
■ प्राकृतिक संसाधन एवं आधारभूत ढांचा	87-89
■ भारतीय अर्थव्यवस्था का सामाजिक क्षेत्र	89-112
■ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन	112-123
■ विविध	124-138

भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार

■ विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्न	139-167
--	---------

जनगणना एवं नगरीकरण

■ जनसांख्यिकी (Demographics).....	168-199
■ भारतीय जनसंख्या (Indian Population)	168
■ भारतीय नगरीकरण (Indian Urbanization)	184
■ विश्व जनसंख्या (World Population).....	192
■ विश्व नगरीकरण (World Urbanization)	194
■ विविध (Miscellaneous)	195

प्रश्न-पत्रों का विश्लेषण

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पूर्व परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्न-पत्रों का विश्लेषण चार्ट

क्र.	परीक्षा का नाम एवं परीक्षा वर्ष	कुल परीक्षा प्रश्न
	उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग	
A.	U.P. P.C.S. (Pre)	
	वर्ष 1991-1997	$8 \times 120 = 960$
	वर्ष 1998-2022	$25 \times 150 = 3750$
	वर्ष 2004 Spl., 2008 Spl., 2015 पुनर्परीक्षा	$3 \times 150 = 450$
B.	U.P. P.C.S. (Mains)	
	वर्ष 2002-2016 (2002, 2003 में 1-1 प्रश्न-पत्र तथा 2004-2017 में 2-2 प्रश्न-पत्र)	$30 \times 150 = 4500$
	वर्ष 2004 Spl., 2008 Spl. (प्रत्येक के दो प्रश्न-पत्र)	$4 \times 150 = 600$
C.	U.P. UDA/LDA/RO/ARO (Pre & Mains) Exam.	
	U.P. UDA/LDA (Pre) 2001	$1 \times 150 = 150$
	U.P. UDA/LDA (Pre) 2006	$1 \times 100 = 100$
	U.P. RO/ARO (Pre) 2010	$1 \times 120 = 120$
	U.P. RO/ARO (Pre) 2010 Spl.	$1 \times 140 = 140$
	U.P. RO/ARO (Pre) 2013	$1 \times 140 = 140$
	U.P. RO/ARO (Pre) 2014	$1 \times 140 = 140$
	U.P. RO/ARO (Pre) 2016 (निरस्त)	$1 \times 140 = 140$
	U.P. RO/ARO (Pre) 2017	$1 \times 140 = 140$
	U.P. RO/ARO (Pre) Re-exam 2016	$1 \times 140 = 140$
	U.P. RO/ARO (Pre) 2021	$1 \times 140 = 140$
	U.P. RO/ARO (Mains) 2010	$1 \times 120 = 120$

	U.P. RO/ARO (Mains) 2010 Spl.	$1 \times 120 = 120$
	U.P. RO/ARO (Mains) 2013	$1 \times 120 = 120$
	U.P. RO/ARO (Mains) 2014	$1 \times 120 = 120$
	U.P. RO/ARO (Mains) 2017	$1 \times 120 = 120$
	U.P. RO/ARO (Mains) 2016 (2020)	$1 \times 120 = 120$
	U.P. RO/ARO (Mains) 2021	$1 \times 120 = 120$
D.	U.P. Lower Subordinate (Pre & Mains) Exam.	
	U.P. Lower Subordinate (Pre) 1998	$1 \times 100 = 100$
	U.P. Lower Subordinate (Pre) 2002	$1 \times 100 = 100$
	U.P. Lower Subordinate (Pre) 2002 Spl.	$1 \times 100 = 100$
	U.P. Lower Subordinate (Pre) 2003	$1 \times 100 = 100$
	U.P. Lower Subordinate (Pre) 2004	$1 \times 100 = 100$
	U.P. Lower Subordinate (Pre) 2004 Spl.	$1 \times 100 = 100$
	U.P. Lower Subordinate (Pre) 2008	$1 \times 100 = 100$
	U.P. Lower Subordinate (Pre) 2009	$1 \times 100 = 100$
	U.P. Lower Subordinate (Pre) 2013	$1 \times 150 = 150$
	U.P. Lower Subordinate (Pre) 2015	$1 \times 150 = 150$
	U.P. Lower Subordinate (Mains) 2013	$1 \times 120 = 120$
	U.P. Lower Subordinate (Mains) 2015	$1 \times 120 = 120$
E.	U.P.P.S.C. राजस्व निरीक्षक (प्री.) परीक्षा 2014	$1 \times 100 = 100$
F.	U.P.P.S.C. वन संरक्षक अधिकारी परीक्षा	
	उत्तर प्रदेश वन संरक्षक परीक्षा 2013	$3 \times 150 = 450$
	उत्तर प्रदेश वन संरक्षक परीक्षा 2015	$3 \times 150 = 450$
	उत्तर प्रदेश वन संरक्षक परीक्षा 2017	$3 \times 150 = 450$
	उत्तर प्रदेश वन संरक्षक परीक्षा 2018, 2019, 2020, 2021	$8 \times 150 = 1200$
G.	U.P. PSC खाद्य सुरक्षा अधिनियम परीक्षा, 2013	$1 \times 75 = 75$

H.	U.P. PSC खाद्य एवं सफाई निरीक्षक परीक्षा, 2013	$1 \times 50 = 50$
	U.P.P.S.C. स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी परीक्षा, 2006	$1 \times 150 = 150$
	U.P.P.S.C. कर निरीक्षक अधिकारी परीक्षा, 2003	$1 \times 150 = 150$
	U.P.P.S.C. कर निरीक्षक अधिकारी परीक्षा, 1997	$1 \times 100 = 100$
	U.P.P.S.C. सहायक अभियंता परीक्षा, 2004, 2007, 2007(II), 2008, 2011, 2013	$6 \times 100 = 600$
	U.P.P.S.C. सहायक अभियंता परीक्षा, 2019, 2021	$2 \times 25 = 50$
	U.P.P.S.C. खण्ड शिक्षा अधिकारी (BEO) परीक्षा, 2019	$1 \times 120 = 120$
	UPPSC BEO Re-Exam, 2006 PART-I (Exam Date : 04.07.2009)	$1 \times 100 = 100$
	UPPSC BEO Re-Exam, 2006 PART-II (Exam Date : 04.07.2009)	$1 \times 100 = 100$
	UPPSC SDI Exam 2006 PART-I (Exam Date : 27.07.2008)	$1 \times 100 = 100$
	UPPSC SDI Exam 2006 PART-II (Exam Date : 27.07.2008)	$1 \times 100 = 100$
	UPPSC SDI Exam 2003 (Exam Date : 15.11.2005)	$1 \times 75 = 75$
	UPPSC यूनानी स्वास्थ्य अधिकारी परीक्षा, 2016 (Exam Date : 22.01.2020)	$1 \times 30 = 30$
	UPPSC यूनानी स्वास्थ्य अधिकारी परीक्षा, 2018 (Exam Date : 25.07.2021)	$1 \times 30 = 30$
	UPPSC GDC प्रवक्ता परीक्षा, 2020 (15-03-2022)	$1 \times 40 = 40$
	UPPSC GDC प्रवक्ता परीक्षा, 2017 (3-11-2019)	$1 \times 30 = 30$
	UPPSC GDC प्रवक्ता परीक्षा, 2013 (27-12-2014)	$1 \times 30 = 30$
	UPPSC सहायक सारियकी अधिकारी परीक्षा, 2014 (11-11-2018)	$1 \times 30 = 30$
	UPPSC ADO परीक्षा, 2014	$1 \times 30 = 30$
	UPPSC मेडिकल ऑफिसर परीक्षा, 2021 (31.07.2022)	$1 \times 30 = 30$
	UPPSC मेडिकल ऑफिसर परीक्षा, 2018 (30-09-2018)	$1 \times 30 = 30$
	UPPSC डायट (DIET) प्रवक्ता परीक्षा, 2014 (15-03-2015)	$1 \times 30 = 30$
	UPPSC GIC प्रवक्ता परीक्षा, 2021 (19-09-2021)	$1 \times 40 = 40$
	UPPSC GIC प्रवक्ता परीक्षा, 2017 (23-09-2018)	$1 \times 30 = 30$
	UPPSC GIC एल.टी.ग्रेड भर्ती परीक्षा, 2018 (29-07-2018)	$1 \times 30 = 30$
	UPPSC GIC प्रवक्ता परीक्षा (शि.वि.), 2015 (25-09-2016)	$1 \times 30 = 30$

	UPPSC GIC प्रवक्ता परीक्षा, 2015 (15-09-2015)	$1 \times 30 = 30$
	UPPSC पॉलिटेक्निक लेक्चरर परीक्षा, 2020 (22-03-2022)	$1 \times 25 = 25$
	UPPSC पॉलिटेक्निक लेक्चरर परीक्षा, 2020 (12-12-2021)	$1 \times 25 = 25$
	UPPSC आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा, 2021 (26-09-2021)	$1 \times 40 = 40$
	UPPSC आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा, 2015 (04-10-2015)	$1 \times 30 = 30$
	UPPSC GIC प्रवक्ता परीक्षा, 2012 (14-06-2015)	$1 \times 30 = 30$
	UPPSC आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा, 2012 (02-06-2015)	$1 \times 30 = 30$
	UPPSC GIC प्रवक्ता परीक्षा, 2009 (22-05-2015)	$1 \times 30 = 30$
	UPPSC आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा, 2009 (12-05-2015)	$1 \times 30 = 30$
	UPPSC राज्य कृषि सेवा परीक्षा, 2020 (01-08-2021)	$1 \times 40 = 40$
	UPPSC स्टॉफ नर्स परीक्षा, 2017, 2021 (03-10-2021), 2022 (10.04.2022)	$3 \times 30 = 90$
	UPPSC विधिक्षण अधिकारी परीक्षा, 2020	$1 \times 40 = 40$
	UPPSC APS परीक्षा, 2007, 2013	$2 \times 100 = 200$
	UPPSC पशु चिकित्सा अधिकारी परीक्षा, 2020 (15.05.2022)	$1 \times 30 = 30$
	UPPSC सहायक रेडियो अधिकारी परीक्षा, 2018 (28.08.2022)	$1 \times 30 = 30$
	UPPSC कम्प्यूटर सहायक परीक्षा, 2019 (23.08.2020)	$1 \times 25 = 25$
	UPPSC सहायक प्रबंधक (गैर तकनीकी) परीक्षा, 2016 (22.11.2020)	$1 \times 100 = 100$
	वैकल्पिक विषय (Optional Subject) के सामान्य अध्ययन सम्बन्धी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न	
	उत्तर प्रदेश पी.सी.एस. (इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल एवं अन्य) (प्री) परीक्षा 1990-2011	$96 \times 120 = 11520$
	कुल प्रश्न-पत्र = 264	30907

नोट- उपरोक्त प्रश्न-पत्रों के सम्यक विश्लेषण के उपरान्त यथा संभव समान प्रकृति एवं प्रवृत्ति से बचते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या एवं नगरीकरण से सम्बन्धित कुल 3283 प्रश्नों को अध्यायवार प्रस्तुत किया गया है। दुहराव वाले प्रश्नों का परीक्षा वर्ष एवं परीक्षा नाम यथास्थान निर्दिष्ट कर दिया गया है ताकि प्रश्न पूछने की तकनीकि का प्रतियोगियों को लाभ मिल सके।

01.

भारतीय अर्थव्यवस्था

1. भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ

1. भारत ने 'मिश्रित अर्थव्यवस्था' की अवधारणा को निम्नलिखित में किसके अन्तर्गत स्वीकार किया?
- संविधान का निर्माण
 - द्वितीय पंचवर्षीय योजना
 - 1948 की औद्योगिक नीति
 - उपर्युक्त में से कोई नहीं

UPPSC ACF/RFO (Mains) Paper-II 2021

Ans. (b) : भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत स्वीकार किया गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य ऐसी अर्थव्यवस्था से है जिसमें निजी तथा सरकारी दोनों क्षेत्रों का सह-अस्तित्व होता है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। प्रो. जॉन मेनार्ड कीस को मिश्रित अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है।

2. मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है-

- आधुनिक एवं परम्परागत क्षेत्रों का सह अस्तित्व
- सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व
- स्वदेशी एवं विदेशी क्षेत्र का सह अस्तित्व
- आधुनिक और परम्परागत समाज का अस्तित्व

उत्तर-(b) UPPCS (Pre) Economics Opt. 1992

UPPCS (Pre.) G.S. 2003

UP UDA/LDA (Pre) G.S., 2006

UPPCS (Mains) G.S. Ist 2007

व्याख्या- उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

3. भारतीय अर्थव्यवस्था एक "मिश्रित अर्थव्यवस्था" है, क्योंकि इसमें मिश्रण है।

- ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों का
- सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का
- विशाल स्तरीय तथा लघु स्तरीय उद्योग का
- भारतीय तथा विदेश उपकरणों का

उत्तर-(b) UPPCS Tax Inspector-2003

व्याख्या- उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

4. निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है?

- पूँजीवादी अर्थव्यवस्था
- समाजवादी अर्थव्यवस्था
- मिश्रित अर्थव्यवस्था
- उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर-(c) UPPCS (Pre) 2015

व्याख्या- उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

5. भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है—

- गांधीवादी व्यवस्था पर
- समाजवादी व्यवस्था पर
- पूँजीवादी व्यवस्था पर
- मिश्रित अर्थव्यवस्था पर

उत्तर-(d) UPPCS (Pre) G.S. 2007

व्याख्या- उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

6. भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है –

- पिछड़ी हुई
- विकसित
- विकासशील
- अल्पविकसित

उत्तर-(c) UPPCS (Pre) G.S. 1995

व्याख्या- उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

7. विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है?

- व्यक्ति
- राज्य
- व्यक्ति और राज्य दोनों
- उपर्युक्त में से किसी की नहीं

उत्तर - (c) UP RO/ARO (Pre) G.S., 2013

व्याख्या – विकास का भारतीय मॉडल व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों की सुरक्षा करता है, इस कथन की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि, भारत में अर्थव्यवस्था के विकास के लिये मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वरूप अपनाया गया है।

8. बन्द अर्थव्यवस्था (क्लोज्ड इकोनॉमी) से आप क्या समझते हैं—

- निर्यात बन्द
- आयात-निर्यात बन्द
- आयात बन्द
- निर्यात्रित पूँजी

उत्तर-(b) UPPCS (Pre.) G.S. 1991

व्याख्या-ऐसी अर्थव्यवस्थायें जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था में किसी अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी का हस्तक्षेप न हो अर्थात् विश्व के देशों के साथ व्यापार न होकर देश में ही व्यापार अधिक होता हो उसे बन्द अर्थव्यवस्था (closed economy) कहते हैं। बंद अर्थव्यवस्था में आयात-निर्यात बिल्कुल बंद रहता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था इसका विशिष्ट उदाहरण है परन्तु आजकल यह अर्थव्यवस्था भी बाजार की शक्तियों से प्रभावित रही है। वर्तमान में कोई भी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था नहीं रह गयी है।

9. भारतीय अर्थव्यवस्था है

- (a) प्रिश्नित अर्थव्यवस्था
- (b) समाजवादी अर्थव्यवस्था
- (c) पूँजीवादी अर्थव्यवस्था
- (d) गांधीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था

उत्तर-(a)

UP PSC RO/ARO (Mains) 2016

व्याख्या—उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

10. भारतीय अर्थव्यवस्था है—

- (a) विकसित
- (b) अविकसित
- (c) विकासशील
- (d) पिछड़ी हुई

उत्तर-(c)

UPPCS (Pre) Economics Opt. 1993

व्याख्या : भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है। अर्थात् विकास की प्रक्रिया में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश ने एक अल्पविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में जो विकास यात्रा शुरू किया, उसमें अनेक संरचनात्मक परिवर्तन हुए तथा उसमें विकसित देशों के भी लक्षण आये। परन्तु अब भी इसमें विकसित तथा अल्पविकसित देशों के लक्षणों का मिश्रण है, इसलिए इसे विकासशील देश कहना उचित है। भारतीय अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित आधारभूत लक्षण हैं— (1) कृषि की प्रधानता, (2) विशाल जनसंख्या, (3) निम्न प्रतिव्यक्ति आय, (4) पूँजी का अभाव, (5) कृषि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव, (6) असंतुलित आर्थिक विकास, (8) औद्योगिकीकरण हुआ है, पर अब भी पिछड़ा है, (9) आर्थिक कुचक्रों का जोर एवं (10) परम्परावादी समाज।

11. भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है—

- I. कृषि की प्रधानता
- II. उद्योग की प्रधानता
- III. न्यून प्रति व्यक्ति आय
- IV. बृहद बेरोजगारी

नीचे लिखे कूट से सही उत्तर चुनिये :

कूट :

- (a) I वा II केवल
- (b) I, II व III केवल
- (c) II, III व IV केवल
- (d) I, III व IV केवल

उत्तर-(d)

UPLower (Pre) Spl. G.S. 2004

व्याख्या—उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

12. निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है?

- (a) धन की न्यून कार्य क्षमता
- (b) प्रति व्यक्ति कम आय

(c) पूँजी निर्माण की न्यून दर

(d) प्राकृतिक संसाधनों की कमी

उत्तर-(d)

UPPCS (Mains) Spl. G.S. Ist 2004

व्याख्या—भारत में प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है। भारत में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन विद्यमान है।

13. निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती हैं?

- 1. कृषि मुख्य व्यवसाय
- 2. प्रच्छन्न बेरोजगारी
- 3. मानव पूँजी की निम्न गुणवत्ता
- 4. प्रोटीन का प्रतिव्यक्ति सेवन उच्च होना

नीचे दिये गये कूटों से सही उत्तर चुनिये :

कूट :

- (a) केवल 1 तथा 2
- (b) 1 तथा 4
- (c) केवल 2 तथा 3
- (d) 1, 2 तथा 3

उत्तर-(d)

UPPCS (Mains) GS 2017 IInd

व्याख्या—प्रोटीन का प्रतिव्यक्ति सेवन उच्च होना विकसित देशों या अर्थव्यवस्थाओं की विशेषता है। शेष के लिए उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

14. अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यतया विशेषता होती है:

- 1. प्रति व्यक्ति निम्न आय
- 2. पूँजी निर्माण की निम्न दर
- 3. निम्न आश्रितता अनुपात
- 4. तृतीयक क्षेत्र में अधिक कार्यबल शक्ति का होना।

नीचे दिये गये कूटों से सही उत्तर चुनिये:

कूट :

- | | |
|-------------|-------------|
| (a) 1 तथा 2 | (b) 2 तथा 3 |
| (c) 3 तथा 4 | (d) 1 तथा 4 |

उत्तर-(a)

UPPCS (Mains) GS 2017 IInd

व्याख्या—अल्प विकसित अर्थव्यवस्था शब्द ऐसे राष्ट्रों के लिए प्रयोग किया जाता है जहाँ के लोगों का रहन-सहन का स्तर काफी नीचा होता है क्योंकि वहाँ पर उत्पादकता का स्तर कम एवं जनसंख्या का स्तर अधिक होने से प्रति व्यक्ति आय का स्तर निम्न पाया जाता है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं भी हैं—निम्न जीवन स्तर, निम्न प्रति व्यक्ति आय, जनसंख्या वृद्धि की ऊँची दर, बेरोजगारी, पूँजी निर्माण की निम्न दर परिसम्पत्तियों का दोषपूर्ण वितरण, अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र (प्राथमिक क्षेत्र) का आधिपत्य। कुछ अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं में अपनी गरीबी कम करने, आय के स्तर को बढ़ाने का सामर्थ्य पाया जाता है इसलिए उन्हें विकासशील अर्थव्यवस्थाएं भी कहते हैं।

02.

आर्थिक विकास एवं नियोजन

1. निम्नलिखित में से कौन-सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है?
- पूँजी का संचय एवं तकनीक सुधार
 - जनसंख्या में परिवर्तन
 - विशेषाकृत क्रियाओं/गतिविधियों में श्रम विभाजन
 - तकनीकविद् एवं नौकरशाह

UPPCS (Pre) 2021

Ans. (d) : तकनीकविद् एवं नौकरशाहों को आर्थिक विकास के प्रमुख कारकों में शामिल नहीं किया जाता है। जबकि पूँजी के संचय व तकनीक सुधार, जनसंख्या में परिवर्तन तथा विशेषाकृत गतिविधियों में श्रम विभाजन आर्थिक विकास के प्रमुख कारकों में शामिल हैं।

2. निम्नलिखित में से कौन-सा एक आर्थिक वृद्धि का अच्छा सूचक है?
- चालू कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद
 - स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद
 - चालू कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद
 - स्थिर कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद

UPPSC Husbandary Medical Officer 2021

Ans. (b) : स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद आर्थिक वृद्धि का अच्छा सूचक है। स्थिर कीमतों या किसी आधार वर्ष के आधार पर व्यक्त आय को वास्तविक आय कहा जाता है। साधन लागत पर व्यक्त वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय को सामान्यतया आर्थिक संवृद्धि के माप के रूप में स्वीकार किया जाता है। किन्तु चूँकि प्रतिव्यक्ति आय की गणना करते समय जनसंख्या को भी ध्यान में रखा जाता है, इसलिए प्रतिव्यक्ति आय की वृद्धि को ही आर्थिक संवृद्धि की माप के लिए स्वीकार किया जाता है। एच.डी.आर. 2010 में प्रतिव्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय को आर्थिक संवृद्धि के मापक के रूप में स्वीकार किया गया है।

3. किसी देश की आर्थिक संवृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदण्ड है, उसका—
- सकल घरेलू उत्पाद
 - निवल घरेलू उत्पाद
 - निवल राष्ट्रीय उत्पाद
 - प्रति व्यक्ति वास्तविक आय

उत्तर-(d)

UP Lower (Pre) G.S. 2013

UPPCS (Pre) G.S. 2013

व्याख्या—

$$\text{प्रति व्यक्ति आय} = \frac{\text{राष्ट्रीय आय}}{\text{जनसंख्या}}$$

प्रति व्यक्ति आय से कर, मूल्य हास निकाल देने पर प्रति व्यक्ति वास्तविक आय प्राप्त होती है।

किसी भी देश के आर्थिक संवृद्धि का वास्तविक मापक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय ही है। चूँकि आर्थिक संवृद्धि का अर्थ किसी देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि से होता है, अतः इसके लिए प्रति व्यक्ति आय ही वास्तविक मापक है।

4. पी.पी.पी. रेटिंग के आधार पर विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थान है—
- दूसरा
 - चौथा
 - छठा
 - दसवाँ

उत्तर—(b) UPPCS (Mains) G.S. Ist 2005

व्याख्या—प्रश्नकाल में पी.पी.पी. रेटिंग के आधार पर विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थान चौथा था।

विश्व बैंक के ताजा आकलन के अनुसार वर्तमान में पी.पी.पी. रेटिंग के आधार पर भारत का स्थान चीन तथा अमेरिका के बाद तीसरा है।

5. संतुलित विकास से तात्पर्य है :
- अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में समान रूप से विकास होता है
 - अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में समान वृद्धि दर हो
 - अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में आवंटित साधनों में समान वृद्धि हो
 - विभिन्न क्षेत्रों का समान दर से विकास हो

उत्तर—(a) UPPCS (Pre) Economics Opt. 1996

व्याख्या : संतुलित विकास से तात्पर्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में समान रूप से विकास होने से है। इसके लिए आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था में एक साथ बहुत अधिक मात्रा में विनियोग किया जाय। किन्तु ये आवश्यक नहीं हैं कि सभी क्षेत्र एक ही दर से बढ़ें। संतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्री नक्स, रोड़ॉन, फ्रैंडरिकलिस्ट, लेविस, सिटोवर्स्की, एलिनयंग तथा लीविन्स्टीन इत्यादि हैं।

6. सूची—I को सूची—II से सुमेलित कीजिए तथा सूची—II को सूची—I से तात्पर्य कीजिए—

सूची—I

- आर्थिक विकास
- आर्थिक वृद्धि
- संपोषित विकास
- जीवन की गुणवत्ता

सूची—II

- सकल घरेलू उत्पाद
- पर्यावरण
- स्वास्थ्य
- संरचनात्मक परिवर्तन

कूट :

A	B	C	D	A	B	C	D
(a) 1	2	3	4	(b) 4	2	3	1
(c) 3	4	1	2	(d) 4	1	2	3

उत्तर—(d) UP UDA/LDA Spl. (M) G.S., 2010

व्याख्या — आर्थिक विकास से संरचनात्मक परिवर्तन होता है। जबकि आर्थिक वृद्धि से तात्पर्य सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि से है। संपोषित विकास पर्यावरण से संबंधित है तथा जीवन की गुणवत्ता स्वास्थ्य से सम्बन्धित है। जीवन की गुणवत्ता अर्थात् स्वास्थ्य को मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित किया जाता है। इस सूचकांक में स्वास्थ्य, शिक्षा व आय को सम्मिलित किया जाता है।

7. समावेशी संवृद्धि के लिए आवश्यक है—
 (a) अधः संरचनात्मक सुविधाओं का विकास
 (b) कृषि का पुनरुद्धार
 (c) शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता
 (d) उपरोक्त सभी

उत्तर—(d) UPPCS (Mains) G.S. IInd Paper 2008

व्याख्या—11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012) का मुख्य लक्ष्य ‘तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास’ रखा गया था। तीव्रतर आर्थिक विकास के साथ समावेशी विकास जिसमें विकास की धारा के साथ सबको जोड़ना तथा आर्थिक विकास से सभी का लाभान्वित होना सुनिश्चित करना था। समावेशी संवृद्धि के लिए अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता की आवश्यकता है।

8. कथन (A) : वास्तविक राष्ट्रीय आय में निरन्तर वृद्धि आर्थिक संवृद्धि की द्योतक है।
 कारण (R) : राष्ट्रीय आय की वृद्धि आवश्यक रूप से प्रति व्यक्ति आय को नहीं दर्शाती है
 नीचे दिये गये कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिये—
कूट :
 (a) A और R दोनों सही है तथा R, A का सही स्पष्टीकरण है।
 (b) A तथा R दोनों सही हैं पर R, A का स्पष्टीकरण नहीं है।
 (c) A सही है, परन्तु R गलत है।
 (d) A गलत है, परन्तु R सही है।

उत्तर—(b) UPPCS (Pre) Economics Opt. 2003

व्याख्या : A तथा R दोनों सही हैं पर R, A का स्पष्टीकरण नहीं है। आर्थिक संवृद्धि से अभिप्राय किसी समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय में वृद्धि से है। आर्थिक संवृद्धि आर्थिक क्रियाओं में परिमाणात्मक परिवर्तन से सम्बन्धित होती है अर्थात् सामान्यतया यदि किसी अर्थव्यवस्था में सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति उत्पाद के आकार में वृद्धि हो रही हो तो यह कहा जाता है कि आर्थिक संवृद्धि हो रही है। राष्ट्रीय आय में सिर्फ प्रति व्यक्ति आय को ही नहीं सम्मिलित करते हैं बल्कि कई अन्य कारक भी हैं। अतः राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि होगी, वह कई कारकों में वृद्धि का परिणाम होगी। अतः कथन और कारण दोनों सही हैं, परन्तु कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

9. निम्न में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है?
 (a) राष्ट्रीय आय की ऊँची वृद्धि दर
 (b) ग्रामीण विकास
 (c) कृषि विकास
 (d) कृषकों को पर्याप्त साधन

उत्तर—(a) UP RO/ARO (Pre) G.S., 2013

व्याख्या—मात्र राष्ट्रीय आय की ऊँची वृद्धि दर से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती है क्योंकि समावेशित विकास एक तरह से व्यापक व वृहद् रूप से विकास की अवधारणा है।

10. निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए :

कथन (A) : आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है।

कारण (R) : वर्तमान भारत सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केन्द्रित कर रही है।

कूट :

(a) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है।

(b) (A) और (R) दोनों सही हैं, किन्तु (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(c) (A) सही है, किन्तु (R) गलत है।

(d) (A) गलत है, किन्तु (R) सही है।

उत्तर—(c) UPPCS (Pre.) Re-exam. 2015

व्याख्या—आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है। यह सत्य है और कारण (R) गलत है क्योंकि भारत सरकार सामान्यतया सभी आर्थिक विषयों पर ध्यान केन्द्रित कर रही है, जबकि प्रश्न में मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केन्द्रित करने की बात की गयी है। अतः सही उत्तर विकल्प (c) होगा।

आर्थिक विकास के अन्तर्गत उत्पादन के साधनों का कुशलतापूर्वक विदोहन होता है। उसके फलस्वरूप राष्ट्रीय आय एवं प्रतिव्यक्ति आय में निरंतर एवं दीर्घकालिक वृद्धि होती है तथा लोगों का जीवन स्तर ऊँचा उठता है।

11. भारत के सन्दर्भ में विकास की हिन्दू दर का विचार किसने दिया—

(a) राजकृष्ण (b) विश्वैसरेया
 (c) पी. आर. ब्रह्मानन्द (d) इन्द्राणी रहमान

उत्तर—(a) UPPCS (Pre) Economics Opt. 1991, 1997

व्याख्या : भारत के संदर्भ में विकास की हिन्दू दर का विचार प्रो। राजकृष्णा ने वर्ष 1981 में दिया था। प्रो। राजकृष्णा का मानना था कि भारतीय अर्थव्यवस्था निम्न आर्थिक संवृद्धि के संतुलन जाल में उलझ कर रह गयी, जो 3.5% प्रतिवर्ष की संवृद्धि दर थी। अर्थव्यवस्था की अन्तर्निहित अपरिवर्तीयता का यह सूचक हिन्दू जीवन शौली के ही समान थी। प्रो। राजकृष्णा का यह विश्लेषण स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम तीन दशकों की संवृद्धि दरों पर आधारित था जो कि वर्ष 1950–1980 बीच औसतन 3.5% था।

12. पिछड़े देशों के लिए ‘रोलिंग प्लान’ का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था?

(a) जी. मिर्डल द्वारा (b) डब्लू.ए. लेविस द्वारा
 (c) आर. नर्स द्वारा (d) ए. सैमुअलसन द्वारा

उत्तर—(a) UPPCS (Mains) G.S. Ist Paper 2004

व्याख्या—आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देशों के योजनागत विकास हेतु गुन्नार मिर्डल द्वारा “रोलिंग प्लान” (अनवरत योजना) का सुझाव दिया गया। भारत में जनता पार्टी सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना को एक वर्ष पूर्व समाप्त करके 1 अप्रैल, 1978 को “रोलिंग प्लान” को लागू किया था। इस योजना की अवधि भारत में केवल एक वर्ष थी। इस योजना का सृजन 1 अप्रैल, 1978 से 31 मार्च, 1983 तक के लिए किया गया था परन्तु 1980 में जनता पार्टी की सरकार के पतन के साथ ही यह योजना भी समाप्त कर दी गई है।

13. अनवरत योजना भारत में लागू की गई
 (a) 1966–67 में (b) 1969–70 में
 (c) 1978–79 में (d) 1989–90 में
- उत्तर-(c) UPPCS (Pre) Economics Opt. 2008

व्याख्या : अनवरत योजना (रोलिंग प्लान) भारत में 1978–79 में लागू की गई। अनवरत योजना जनता सरकार द्वारा 1978 से 1980 तक चलाई गयी। यह योजना गुन्नार मिर्डल द्वारा प्रतिपादित Rolling Plan पर आधारित थी। इसी योजना में Trysem (ट्राईसेम) की शुरुआत की गई।

14. नियोजन पूर्वापेक्षित समझा गया –
 1. संतुलित सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये।
 2. विकास के लाभ समरूप में विस्तृत करने के लिये।
 3. आंचलिक विषमताओं को दूर करने पर ध्यान केन्द्रित करने के लिये।
 4. उपलब्ध संसाधनों के उपयोग को अधिकतम बनाने के लिये।
 नीचे दिये गये कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

कूट :

- | | |
|---------------|---------------|
| (a) 1 और 2 | (b) 1, 2 और 3 |
| (c) 2, 3 और 4 | (d) सभी चारों |

उत्तर-(d) UPPCS (Pre) G.S. 2009

व्याख्या – भारत में आर्थिक नियोजन के प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित हैं–
 • आर्थिक विकास को बढ़ावा देना
 • सामाजिक न्याय
 • पूर्ण रोजगार की प्राप्ति
 • गरीबी निवारण एवं रोजगार अवसरों का सृजन
 • आत्मनिर्भरता की प्राप्ति
 • निवेश एवं पूँजी निर्माण को बढ़ावा
 • आय वितरण एवं क्षेत्रीय विषमता दूर करना
 • आधुनिकीकरण जिसे छठीं योजना में लागू किया गया
 • मानव संसाधन विकास

15. आर्थिक योजना किस में सम्मिलित है–
 (a) केन्द्रीय सूची में (b) राज्य सूची में
 (c) समवर्ती सूची में (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
- उत्तर-(c) UP PSC ACF/RFO (Mains) 2019 Paper I

व्याख्या – आर्थिक योजना समवर्ती सूची में सम्मिलित है। वर्तमान में इसमें 52 विषय (मूलतः 47) हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के तहत पाँच विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया है वे हैं - शिक्षा, बन, नाप-तौल, वन्यजीवों एवं पक्षियों का संरक्षण तथा न्याय का प्रशासन आदि।

16. किस पंचवर्षीय योजना के दौरान खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का गठन किया गया?
 (a) प्रथम पंचवर्षीय योजना (b) द्वितीय पंचवर्षीय योजना
 (c) तृतीय पंचवर्षीय योजना (d) पंचम पंचवर्षीय योजना
- उत्तर-(c) UPPCS ACF/RFO (Mains) Paper-II 2021

Ans. (b) : द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-61) के दौरान खादी एवं ग्राम उद्योग अधिनियम 1956 के तहत खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का गठन अप्रैल, 1957 में किया गया। इसका मुख्यालय मुम्बई में है। जिसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में खादी एवं ग्रामोद्योगों की स्थापना विकास के लिए योजना बनाना, प्रचार करना, और सहायता प्रदान करता है।

17. सूची-I को सूची-II के साथ मिलान कीजिए, नीचे दिए गये कूट में से अपने उत्तर चयन कीजिए–

सूची -I	सूची-II
पंचवर्षीय योजना	प्रयुक्त विकास मॉडल

- | | |
|------------|-----------------------|
| A. प्रथम | 1. एस. चक्रवर्ती मॉडल |
| B. द्वितीय | 2. हैरोड-डोमर मॉडल |
| C. तृतीय | 3. अशोक रूद्र मॉडल |
| D. चतुर्थ | 4. महालनोबिस मॉडल |

कूट

- | A | B | C | D |
|-------|---|---|---|
| (a) 1 | 3 | 2 | 4 |
| (b) 2 | 4 | 1 | 3 |
| (c) 3 | 1 | 2 | 4 |
| (d) 2 | 1 | 4 | 3 |

UPPSC RO/ARO (Pre) 2021

Ans. (b) : सही सुमेलित हैं–

सूची (I) (पंचवर्षीय योजना)	सूची (II) (प्रयुक्त विकास मॉडल)
प्रथम	— हैरोड-डोमर मॉडल
द्वितीय	— महालनोबिस मॉडल
तृतीय	— एस. चक्रवर्ती मॉडल
चतुर्थ	— अशोक रूद्र मॉडल

18. भारत की छठी पंचवर्षीय योजना में किस पर सर्वाधिक व्यय किया गया –

- | | | | |
|------------|----------|----------|-----------|
| (a) उद्योग | (b) सेवा | (c) कृषि | (d) ऊर्जा |
|------------|----------|----------|-----------|
- उत्तर-(d) UPPCS (Pre) Economics Opt. 1991

व्याख्या : भारत में 6वीं पंचवर्षीय योजना 1 April, 1980–31 March, 1985 तक चली। इस योजना में विकास दर का लक्ष्य 5.2% रखा गया तथा प्राप्ति 5.4% रही। इस दौरान प्रतिव्यक्ति आय में 3.2% वृद्धि दर्ज की गई। इस योजना में गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन पर विशेष बल दिया गया। यद्यपि गरीबी निवारण को प्राथमिकता 5वीं FYP में दी गई थी परन्तु गरीबी हटाओं का नारा 6वीं योजना में ही दिया गया तथा गरीबी निवारण सम्बन्धी सभी बड़े तथा महत्वपूर्ण कार्यक्रम इसी योजना में शुरू हुए। ग्रामीण बेरोजगार के उन्मूलन से सम्बन्धित कार्यक्रम IRDP, NREP, DWACRA, RLEGPA इसी योजना में लागू किया गया। 6वीं योजना 15 वर्ष की दीर्घ अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई, अतः इसे Perspective planning कहा जाता है। इस योजना में सर्वाधिक व्यय ऊर्जा क्षेत्र (29%) किया गया। इसके बाद खनिज उद्योग 15.5% पर किया गया।

19. उद्योगों के विकास तथा औद्योगीकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी–

- | | | | |
|------------|-------------|-----------|------------|
| (a) चतुर्थ | (b) द्वितीय | (c) तृतीय | (d) सातवीं |
|------------|-------------|-----------|------------|
- उत्तर-(b) UPPCS (Pre.) G.S. 1991

व्याख्या – द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। यह योजना तीव्र एवं बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण पर ध्यान केन्द्रित करते हुए बनाई गई थी। प्रथम योजना में कृषि क्षेत्र में उत्पादन लक्ष्य से अधिक हुआ था। अतः योजनाकारों ने यह विचार किया कि अब भारतीय अर्थव्यवस्था ऐसी स्थिति में पहुँच गई है जिसमें कृषि को अपेक्षाकृत कम प्राथमिकता देकर उद्योगों पर बल दिया जाये।

20. निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में भारत की विकास दर सर्वाधिक हुई थी?

- (a) आठवीं पंचवर्षीय योजना में
- (b) नवीं पंचवर्षीय योजना में
- (c) दसवीं पंचवर्षीय योजना में
- (d) चौथी पंचवर्षीय योजना में

उत्तर-(d)

UPPSC GDC 2013

व्याख्या— पंचवर्षीय योजना	विकासदर (वास्तविक)
आठवीं (1992-97)	6.8%
नौवीं (1997-2002)	5.4%
दसवीं (2002-2007)	7.6%
चौथी (2007-2012)	7.8%

उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर सर्वाधिक थी।

21. किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया?

- (a) पाँचवीं पंचवर्षीय योजना
- (b) छठवीं पंचवर्षीय योजना
- (c) चौथी पंचवर्षीय योजना
- (d) सातवीं पंचवर्षीय योजना

उत्तर-(a)

UPPSC BEO GS- 2003

व्याख्या— पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-1979) का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया। पहली बार गरीबी-उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया।

22. 'गरीबी उन्मूलन' का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था?

- (a) द्वितीय पंचवर्षीय योजना
- (b) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना
- (c) पंचम पंचवर्षीय योजना
- (d) छठी पंचवर्षीय योजना

उत्तर-(c)

UPPCS (Pre) G.S. 2007, 2004

UPPCS (Mains) G.S. Ist Paper, 2016

व्याख्या—उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

23. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पूरे देश में निम्नलिखित में से किस योजना में फैला?

- (a) चतुर्थ योजना
- (b) पाँचवीं योजना
- (c) छठी योजना
- (d) आठवीं योजना

उत्तर-(c)

UPPCS BEO GS 2006

व्याख्या— समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पूरे देश में छठीं पंचवर्षीय योजना (1980-85) में फैला। इस कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा सन् 1980 के दौरान लागू किया गया था। IRDP का उद्देश्य गरीबों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ-साथ उनके कौशल को विकसित करने का अवसर प्रदान करना है।

24. दुर्गापुर, भिलाई और राऊरकेला स्टील संयंत्र स्थापित किए गए थे—

- (a) प्रथम पंचवर्षीय योजना में
- (b) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में
- (c) तृतीय पंचवर्षीय योजना में
- (d) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में

उत्तर-(b)

UPPSC AE-2007 II

व्याख्या— राऊर केला, भिलाई और दुर्गापुर स्टील संयंत्र की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। राऊरकेला जर्मनी के सहयोग से दुर्गापुर (प. बंगाल) ब्रिटेन के सहयोग से भिलाई इस्पात संयंत्र रूपस के सहयोग से स्थापित किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारी उद्योगों एवं आधारभूत उद्योगों का विकास करना था। यह योजना महालनेबिस योजना पर आधारित थी। इस योजना का लक्ष्य 4.5% निर्धारित था लेकिन वास्तविक वृद्धि दर 4% की थी।

25. भारत में 'अनवरत योजना' किस वर्ष में कार्यशील थी?

- (a) 1968-69
- (b) 1978-79
- (c) 1988-89
- (d) 1990-91

उत्तर-(b) UPPCS (Mains) G.S. IInd Paper 2007

व्याख्या— जनता पार्टी की सरकार ने पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-78) को चार वर्ष बाद ही समाप्त कर दिया और 1978 में अनवरत योजना चालू किया। यह अनवरत योजना 1978-79 तक चला। पुनः कंग्रेस पार्टी की सरकार आने पर अनवरत योजना को समाप्त कर दिया गया और छठीं पंचवर्षीय योजना (1980-85) को प्रारम्भ किया।

26. भारत में योजना के आरम्भ के किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या है—

- (a) 6
- (b) 7
- (c) 5
- (d) 3

उत्तर-(b) UPPCS (Pre.) G.S. 1999

व्याख्या—भारत में योजना के आरंभ के किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या 7 है।

1. प्रथम 1966-69

2. रोलिंग प्लॉन 1978-80

3. तृतीय 1990-92

27. किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया?

- (a) तीसरी में
- (b) पाँचवीं में
- (c) सातवीं में
- (d) नवीं में

उत्तर-(a) UPPCS (Mains) G.S. Ist Paper 2004

व्याख्या—तीसरी पंचवर्षीय योजना भारत की सर्वाधिक असफल योजना मानी जाती है। इस योजना की असफलता का प्रमुख कारण इस समयावधि में उत्पन्न भयंकर सूखे की स्थिति तथा चीन (1962) व पाकिस्तान (1965) के साथ विनाशकारी युद्ध थे। सूखे के परिणामस्वरूप तृतीय योजनाकाल में कृषि में मात्र 2.6 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई जबकि इसके पूर्व के दशक (1950-60 ई.) में कृषि विकास की वार्षिक वृद्धि दर लगभग 4 प्रतिशत थी। इस प्रकार तीसरी योजना में विगत वर्षों तुलना में विकास दर ऋणात्मक रही। तीसरी योजना में कृषि क्षेत्र में (-0.73) प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर्ज हुई।

28. विकास केन्द्र उपागम किस योजना के अन्तर्गत अपनाया गया था?

- (a) प्रथम पंचवर्षीय योजना
- (b) द्वितीय पंचवर्षीय योजना
- (c) तृतीय पंचवर्षीय योजना
- (d) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना

उत्तर-(d) UPPCS (Pre) G.S. 1996

व्याख्या—चौथी योजना (1969–74) का लक्ष्य विकास की गति को तेज करना, कृषि उत्पादन के उत्तर चढ़ाव को नियंत्रित करना तथा विदेशी सहायता की अनिश्चितता के प्रभाव को कम करना था। इसमें समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के कार्यक्रमों के माध्यम से जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की कोशिश की गई है। चौथी योजना में कमज़ोर एवं साधनहीन वर्ग के लोगों की दशा सुधारने तथा विशेष रूप से उनके लिए शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था करने पर विशेष बल दिया गया था।

29. सातवीं योजना में आई.आर.डी.पी. के अंतर्गत रणनीति अपनाई गई थी—

- (a) सम्पूर्ण परिवार का अंगीकरण
- (b) गांवों का अंगीकरण
- (c) विकास खण्ड का अंगीकरण
- (d) जिले का अंगीकरण

उत्तर—(a)

UPPCS (Pre) G.S. 1994

व्याख्या—आई.आर.डी.पी. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (Intigrated Rural Development Programme) की शुरुआत 2 अक्टूबर, 1980 में की गयी। इसके क्रियान्वयन के लिए सम्पूर्ण परिवार का अंगीकरण किया गया है। उदाहरण: सरकार ने गरीबी रेखा को परिभाषित करने के लिए IRDP में परिवार को ही ईकाई (यूनिट) के रूप में चुना है।

30. योजना काल में सर्वाधिक संवृद्धि दर प्राप्त की गई थी—

- (a) आठवीं योजना में
- (b) दसवीं योजना में
- (c) नवीं योजना में
- (d) सातवीं योजना में

उत्तर—(b)

UPPCS (Pre) GS, 2012

**UPPCS (Mains) Spl. G.S. IInd 2008
UPPCS (Mains) G.S. IInd Paper 2009, 2007**

व्याख्या: नीचे दिये गये सारणी से स्पष्ट है कि दिये गये विकल्पों में 10वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक वृद्धि दर प्राप्त की गई थी।

पंचवर्षीय योजना	अवधि	आर्थिक संवृद्धि की दर	
		लक्ष्य (%)	प्राप्ति (%)
प्रथम (I)	1951-56	2.1	3.6
द्वितीय (II)	1956-61	4.5	4.1
तृतीय (III)	1961-66	5.6	2.5
चतुर्थ (IV)	1969-74	5.7	3.3
पंचम (V)	1974-79	4.4	5.0
षष्ठी (VI)	1980-85	5.2	5.4
सप्तम (VII)	1985-90	5.0	5.8
अष्टम (VIII)	1992-97	5.6	6.7
नवम (IX)	1997-2002	6.5	5.5
दशम (X)	2002-07	8	7.6
एकादश (XI)	2007-12	9	7.8
द्वादश (XII)	2012-17	8	6.7

31. निम्नलिखित में से भारत की किस पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत, आर्थिक संवृद्धि दर अपने लक्ष्य से अधिक रही?

- (a) द्वितीय (b) चतुर्थ (c) पंचम (d) आठवीं

उत्तर—(d)

UPPCS (Pre.) G.S. 1998

UPPCS (Pre) Economics Opt. 2009, 2001, 1997, 1993

व्याख्या—उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

32. दशम् पंचवर्षीय योजना की वृद्धि दर का लक्ष्य है—

- (a) 5.5 प्रतिशत
- (b) 6.5 प्रतिशत
- (c) 8.0 प्रतिशत
- (d) 8.5 प्रतिशत

उत्तर—(c)

UP Lower (Pre) G.S. 2002

व्याख्या—उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

33. भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निवेश का स्वरूप निर्धारित किया—

- (a) प्रो. एन. काल्डार ने
- (b) प्रो. वी.के.आर.वी. राव ने
- (c) प्रो. आर.एफ. हैरोड ने
- (d) प्रो. पी.सी. महालनोविस ने

उत्तर—(d)

UPPCS (Pre) Economics Opt. 1995

व्याख्या : भारत का द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निवेश का स्वरूप प्रो. पी.सी. महालनोविस ने निर्धारित किया था, जो 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी—पूर्जीगत वस्तु क्षेत्र, फैक्ट्री उत्पादित उपभोग वस्तु क्षेत्र, लघु इकाई उत्पादन क्षेत्र तथा घेरेलू उद्योग क्षेत्र थे। कृषि सहित एवं सेवा क्षेत्र मॉडल वास्तव में असतुलित विकास रणनीति पर आधारित था। इसमें विकास दर का लक्ष्य 4.5% रखा गया तथा प्राप्ति 4.1% रही। इसी योजना में राउरकेला (उडीसा), भिलाई (छत्तीसगढ़), दुर्गापुर (पं. बंगाल) इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई।

34. राष्ट्रीय हार्टीकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरम्भ किया गया था?

- (a) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में
- (b) दसवीं पंचवर्षीय योजना में
- (c) नवीं पंचवर्षीय योजना में
- (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर—(b)

UPPCS (Mains) G.S. IInd 2009

व्याख्या—बागवानी क्षेत्र के विकास तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान की सम्भावना को दृष्टि में रखते हुए मई, 2005 में सरकार ने कृषि के विविधीकरण तथा उच्च मूल्य वर्धन वाली बागवानी फसलों को उगाने को प्रोत्साहित करने तथा कृषकों के आय में वृद्धि लाने के उद्देश्य से एक प्रमुख प्रयास के रूप में राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM) को प्रारम्भ किया। जबकि इस पंचवर्षीय योजना का समय 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 था। इस प्रकार राष्ट्रीय हार्टीकल्चर मिशन का प्रारम्भ दसवीं योजना में किया गया था।

35. निम्न में से किस क्षेत्र को दसवीं योजना परिव्यय में सर्वाधिक प्रतिशत आवंटित किया गया था?

- (a) कृषि तथा संबंधित क्रियाएं
- (b) सामाजिक सेवाएं
- (c) यातायात
- (d) ऊर्जा

उत्तर—(d)

UPPCS (Mains) G.S. IInd 2005

व्याख्या : दसवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत लगभग एक साल के विलम्ब के साथ 21 दिसम्बर 2002 को राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदन मिलने तथा बाद में केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान करने के साथ हुई। इसकी अवधि 1 अप्रैल, 2002 से 31 मार्च, 2007 निर्धारित की गई है। ज्ञातव्य है कि दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) पर राष्ट्रीय बहस के लिए जारी दृष्टिकोण पत्र के मसौदे में देश के नियोजित अर्थिक-सामाजिक विकास में पहली बार निजी क्षेत्र के लिए बड़ी भूमिका की कल्पना की गई थी। दसवीं योजना के दौरान सर्वाधिक परिव्यय का आवंटन ऊर्जा क्षेत्र में रहा।

36. भारत में योजना अवकाश की अवधि थी—
 (a) 1962–65 (b) 1966–69
 (c) 1969–72 (d) 1972–75
- उत्तर—(b) UPPCS (Pre) Economics Opt. 1996

व्याख्या—तृतीय पंचवर्षीय योजना 31 मार्च, 1966 को समाप्त हो गई थी। तदनुसार चतुर्थ योजना को 1 अप्रैल, 1966 से प्रारम्भ होना चाहिए था, किन्तु तृतीय योजना की दुर्भाग्यपूर्ण असफलता के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन लगभग स्थिर हो गया था। जून, 1966 में भारत सरकार द्वारा भारतीय रुपए के अवमूल्यन (Devaluation) की घोषणा की गई, ताकि देश के निर्यातों में वृद्धि की जा सके, किन्तु इसके अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं हो सके। अतः चौथी योजना को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया तथा उसके स्थान पर तीन वार्षिक योजनाएँ लागू की गई। कुछ अर्थस्थियों ने तो 1966 से 1969 तक की अवधि को 'योजना अवकाश' (Plan Holiday) की संज्ञा तक दे दी, क्योंकि इस अवधि में कोई नियमित नियोजन नहीं किया गया।

37. ग्यारहवीं योजना के प्रारूप प्रपत्र के अनुसार लक्षित संवृद्धि दर के प्राप्त होने तथा जनसंख्या के 1.5% प्रतिशत वार्षिक वृद्धि होने पर, एक औसत भारतीय की वास्तविक आय दोगुनी हो जाएगी—
 (a) 5 वर्षों में (b) 10 वर्षों में
 (c) 15 वर्षों में (d) 20 वर्षों में
- उत्तर—(b) UPPCS (Pre) G.S. 2008

व्याख्या—ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) प्रपत्र के अनुसार लक्षित संवृद्धि दर प्राप्त होने तथा जनसंख्या के 1.5% वार्षिक वृद्धि होने पर, एक औसत भारतीय की वास्तविक आय 10 वर्ष में दुगुनी हो जाएगी।

38. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक रोजगार के अवसर में वृद्धि की आशा की गई है—
 (a) कृषि में (b) निर्माण कार्यों में
 (c) विनिर्माण में (d) परिवहन तथा संचार में
- उत्तर—(b) UPPCS (Mains) G.S. IInd 2008

व्याख्या—11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) में निर्माण कार्यों में सबसे अधिक रोजगार के अवसरों में वृद्धि की आशा की गई थी और रोजगार के 7 करोड़ नए अवसर सृजित कर निर्धनता अनुपात में 10% की कमी लाने का लक्ष्य इस योजना में निर्धारित किया गया था।

39. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का वर्ष 2012 तक गरीबी अनुपात को कितने प्रतिशत घटाने का लक्ष्य है?
 (a) 2.0 प्रतिशत (b) 2.5 प्रतिशत
 (c) 10.0 प्रतिशत (d) 15.0 प्रतिशत
- उत्तर—(c) UP RO/ARO (Pre) G.S., 2013

व्याख्या—उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

40. 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितने आई.आई.टी. (भारतीय प्रौद्योगिकी के संस्थान) स्थापित किये जायेंगे?
 (a) 6 (b) 7
 (c) 8 (d) 9
- उत्तर—(c) UP UDA/LDA (Pre) G.S., 2006

व्याख्या—ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 30 केन्द्रीय विश्वविद्यालय, आठ आई.आई.टी. (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान), 7 आई.आई.एम. स्थापित किये जाने का लक्ष्य रखा गया था। ज्ञातव्य है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र के लाभों को देखते हुए केन्द्र सरकार सामाजिक विकास क्षेत्र (Social Development Zones—SDZ) प्रारम्भ करने की योजना बनाई है।

41. भारत में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संचयी वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम थी
 (a) आठवीं पंचवर्षीय योजना काल में
 (b) सातवीं पंचवर्षीय योजना काल में
 (c) छठवीं पंचवर्षीय योजना काल में
 (d) पाँचवीं पंचवर्षीय योजना काल में
- उत्तर—(a) UPLower (Pre) Spl. G.S. 2004

व्याख्या—दिये गये विकल्पों में आठवीं पंचवर्षीय योजना में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संचयी वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम थी। इस योजना में 5.6% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था, जबकि प्राप्ति 6.7% की रही।

42. प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का मुख्य कारण था—
 (a) भूमि सुधार (b) मानसून की अनुकूलता
 (c) औद्योगिक विकास (d) सिंचाई के साधनों में वृद्धि
- उत्तर—(b) UPPCS (Pre) Economics Opt. 1992

व्याख्या—प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 April, 1951 से 31 March, 1956 तक थी। यह योजना हैरड-डोमर संवृद्धि मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में ही भाखडा नांगल, दामोदर घाटी एवं हीराकुण्ड जैसी बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं चालू की गयी। इस योजना में कृषि क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। इस योजना में विकास दर का लक्ष्य 2.1% रखा गया तथा प्राप्ति 3.6% रही। इस योजना की सफलता का मुख्य कारण अनुकूल मानसून था। जिसके कारण फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई।

43. निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रमों का मेल कीजिये
- | योजना | कार्यक्रम |
|------------------|---|
| A. प्रथम योजना | 1. तीव्र औद्योगीकरण |
| B. द्वितीय योजना | 2. सामुदायिक विकास |
| C. तृतीय योजना | 3. आधारभूत उद्योगों का प्रसार |
| D. चतुर्थ योजना | 4. न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम |
| E. पंचम योजना | 5. स्वावलम्बन की प्राप्ति एवं स्थिरता के साथ संवृद्धि |

निम्न कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए—

- | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E |
|-------|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|
| (a) 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (b) 2 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| (c) 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | (d) 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
- उत्तर—(d) UPPCS (Pre) G.S. 1994

व्याख्या—सही सुमेल है-

योजना	कार्यक्रम
प्रथम योजना	- सामुदायिक विकास
द्वितीय योजना	- तीव्र औद्योगीकरण
तृतीय योजना	- आधारभूत उद्योगों का प्रसार
चतुर्थ योजना	- स्वावलम्बन की प्राप्ति एवं स्थिरता के साथ संवृद्धि
पंचम योजना	- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

44. स्वस्फूर्ति विकास का उद्देश्य किस योजना में अपनाया गया?
- द्वितीय पंचवर्षीय योजना में
 - तृतीय पंचवर्षीय योजना में
 - चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में
 - पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में
- उत्तर-(b) UPPCS (Pre) Economics Opt. 1999
- व्याख्या :** स्वस्फूर्ति विकास का उद्देश्य तृतीय पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया। तीसरी योजना के ऊपर चक्रवर्ती माडल का प्रभाव देखा जा सकता है परन्तु इस माडल का वास्तव में प्रयोग चौथी योजना में हुआ।
45. आठवीं योजना में जी. डी. पी. की वृद्धि दर प्रतिशत प्रतिवर्ष का लक्ष्य निर्धारित किया गया है –
- 4.8
 - 5.2
 - 5.6
 - 6.0
- उत्तर-(c) UPPCS (Pre) G.S. 1995
- व्याख्या –** आठवीं पंचवर्षीय योजना में वार्षिक विकास दर का लक्ष्य 5.6% निर्धारित किया गया। यह योजना 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक लागू रही। इसमें अधोसंरचना के विकास पर पर्याप्त बल दिया गया। इस योजना का मुख्य ध्येय 'मानव विकास' था।
46. प्रो. पी. सी. महालनोबिस का नाम जुड़ा है :
- प्रथम योजना से
 - द्वितीय योजना से
 - तृतीय योजना से
 - चतुर्थ योजना से
- उत्तर-(b) UPPCS (Pre) Economics Opt. 1996
- व्याख्या :** प्रो. पी.सी. महालनोबिस का नाम द्वितीय योजना से जुड़ा है। द्वितीय योजना की समयावधि 1 April, 1956 से 31 March, 1961 तक थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पी.सी. महालनोबिस द्वारा विकासित 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी। दूसरी योजना में आधार भूत तथा भारी उद्योगों पर विशेष बल के साथ तीव्र औद्योगिकरण को प्रमुख लक्ष्य माना गया। इस योजना में विकास दर का लक्ष्य 4.5 रुचा गया तथा प्राप्ति 4.1% रही।
47. भारत में किस 'पंचवर्षीय योजना' का लक्ष्य 'तीव्र गति से वृद्धि के साथ समावेशी विकास' था?
- बारहवीं
 - ग्यारहवीं
 - दसवीं
 - नौवीं
- उत्तर-(b) UPPCS ACF (Mains)-2017
- व्याख्या-** तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) में प्रारंभ हुई जिसका लक्ष्य तीव्रगति के साथ समावेशी विकास था।
48. भारत में निम्नलिखित पाँच वर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय 'सम्पोषणीय वृद्धि' था?
- 9वीं
 - 10वीं
 - 11वीं
 - 12वीं
- उत्तर-(d) UPPCS (Pre) G.S. 2018
- व्याख्या-** 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) का मुख्य ध्येय 'सम्पोषणीय वृद्धि' था, जबकि 9वीं पंचवर्षीय योजना-न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास, 10वीं पंचवर्षीय योजना-गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना-तीव्रतर एवं समावेशी विकास से सम्बन्धित है।
49. भारत में प्रारम्भ की गई किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय सम्पोषणीय विकास था?
- 10वीं पंचवर्षीय योजना
 - 11वीं पंचवर्षीय योजना
 - 12वीं पंचवर्षीय योजना
 - उपर्युक्त में से कोई नहीं
- उत्तर-(c) U.P. PCS Asst. State Officer-2014
- व्याख्या-** उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
50. नवम् पंचवर्षीय योजना के मसौदा के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर है—
- 6%
 - 6.5%
 - 7.0%
 - 7.5%
- उत्तर-(*) UPPCS (Pre.) G.S. 1998
- व्याख्या-** नवम् पंचवर्षीय योजना के मसौदा के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.0% थी। किन्तु बाद में घटा कर 6.5% कर दिया गया। प्रश्नकाल के दौरान सही उत्तर विकल्प (c) था। 12वीं FYP में GDP में औसत वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य 9% रखा गया था। जिसे घटाकर 8% कर दिया गया था।
51. भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी?
- 1947 में
 - 1949 में
 - 1950 में
 - 1951 में
- उत्तर-(c) UP Lower (Pre.) G.S. 2009
- व्याख्या-** योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था थी, जिसका गठन केंद्रीय मंत्रिमण्डल के एक संकल्प द्वारा 15 मार्च, 1950 को किया गया। इसका मुख्य कार्य केंद्र की पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना तथा राज्यों की वार्षिक योजनाओं के संबंध में सलाह देना था। 1 जनवरी, 2015 को योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया।
52. राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था?
- 1947
 - 1952
 - 1965
 - 1966
- UPPSC Poly. Lect. 22.12.2021
- Ans.(b):** 6 अगस्त, 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना केंद्रीय मंत्रिमण्डल के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद में प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रिमण्डल के सभी सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री व केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि तथा नीति आयोग के सभी सदस्य शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री इस परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद एक महत्वपूर्ण संगठन है जो देश की विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए बाध्य है।
53. राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन में हुआ था।
- 1950
 - 1952
 - 1954
 - उपर्युक्त में से कोई नहीं
- UPPSC RO/ARO (Mains) 2021
- Ans. (b) :** उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
54. भारत में 'राष्ट्रीय विकास परिषद' कब गठित की गई थी?
- 26 जनवरी, 1950
 - 15 मार्च, 1950
 - 6 अगस्त, 1951
 - 6 अगस्त, 1952
- उत्तर-(d) UPPSC GIC Inter 2015
- व्याख्या-** उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
55. योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया?
- नरेन्द्र मोदी
 - मोरारजी देसाई
 - अटल बिहारी वाजपेयी
 - आई. के. गुजराल
- उत्तर-(a) UPPCS (Pre.) 2015
- व्याख्या-** योजना आयोग का अंत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया। नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान) भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है। इसका पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होगा। इसके प्रथम उपाध्यक्ष अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया बनाये गये थे। वर्तमान में सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष है।

- 56.** निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
- भारतीय योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है
 - भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णयन संस्था योजना आयोग है
 - योजना आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद् का सचिव भी होता है
 - भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद् की अध्यक्षता करता है
- उत्तर-(b)** UPPCS (Mains) G.S IInd Paper 2004
UP UDA/LDA (Pre) G.S., 2006
- व्याख्या :** योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद् दोनों आर्थिक नियोजन से सम्बन्धित 'संविधानेतर' राष्ट्रीय संस्थाएँ हैं। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद् नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णयन संस्था है।
- 57.** निम्नलिखित में से कौन सी संविधानेतर संस्था है?
- संघ लोक सेवा आयोग
 - वित्त आयोग
 - योजना आयोग
 - चुनाव आयोग
- उत्तर-(c)** UPPCS (Mains) G.S. IInd Paper 2008
UP RO/ARO (M) G.S., 2013
- व्याख्या –** योजना आयोग एक संविधानेतर निकाय था। अब इसका स्थान नीति आयोग ने ले लिया है। जबकि वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और चुनाव आयोग संवैधानिक निकाय हैं। वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद-280 में, संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान अनुच्छेद-315 में जबकि चुनाव आयोग का उल्लेख अनु.-324 में है।
- 58.** राष्ट्रीय विकास परिषद् मुख्यतः सम्बद्ध है –
- योजनाओं को लागू करने में
 - पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन करने में
 - भारत में मुख्य विकास योजनाओं के अनुमोदन और मूल्यांकन में
 - सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के लागू करने में
- उत्तर-(b)** UPPCS (Mains) G.S. Ist Paper 2008
UPPCS (Mains) G.S IInd Paper 2004
UPPCS Kanoongo Exam., 2014
- व्याख्या –** राष्ट्रीय विकास परिषद् एक गैर सार्विधिक निकाय है, जिसका गठन आर्थिक नियोजन हेतु राज्यों एवं योजना आयोग के बीच सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किया गया था। सरकार ने एक प्रस्ताव द्वारा 6 अगस्त, 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद् का गठन किया। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष तथा योजना आयोग का सचिव ही इसका सचिव होता है। प्रारम्भ में गज्यों के मुख्यमंत्री ही इसके सदस्य होते थे, किन्तु 1967 के बाद से केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासक तथा योजना आयोग के सभी सदस्य भी इस निकाय में शामिल होने लगे। योजना आयोग का कार्य योजना निर्माण तक ही सीमित है, जबकि राष्ट्रीय विकास परिषद् योजना आयोग (अब नीति आयोग) द्वारा तैयार की गई योजना का अध्ययन करके उसे अंतिम स्वीकृति प्रदान करती है। इसकी स्वीकृति के पश्चात् ही योजना का प्रारूप प्रकाशित होता है। के संथानमें ने राष्ट्रीय विकास परिषद् को सर्वोच्च मंत्रिपरिषद् की संज्ञा दी है। ध्यातव्य है 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया।
- 59.** राष्ट्रीय विकास परिषद् का मुख्यतः सम्बन्ध होता है
- पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से
 - ग्राम विकास योजनाओं के क्रियान्वयन से
 - विकास परियोजनाओं के निर्माण से
 - केन्द्र-राज्य वित्तीय सम्बन्ध से
- उत्तर-(a)** UPPCS BEO GS 2006
- व्याख्या –** उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
- 60.** विजन-2020 प्रपत्र (Document) तैयार किया गया था-
- वित्त मंत्रालय द्वारा
 - नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा
 - योजना आयोग द्वारा
 - भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा
- उत्तर-(c)** UPPCS (Pre) G.S. 2004
- व्याख्या –** योजना आयोग द्वारा श्री एस. पी. गुप्ता की अध्यक्षता में गठित कार्यदल द्वारा भारत के अध्ययन के पश्चात् प्रस्तुत इस प्रपत्र में भारत के 20 वर्षीय विकास की योजना प्रस्तुत की गई थी।
- 61.** नीति आयोग की संचालन परिषद् में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है?
- राज्य वित्त मंत्री
 - मुख्य मंत्री
 - राज्यपाल
 - राज्य सरकार के मुख्य सचिव
- UPPSC ACF/RFO (Mains) Paper-I 2021**
- Ans. (b) :** नीति आयोग की संचालन परिषद् में राज्यों का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री और केन्द्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल करते हैं। भारत के परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय संस्थान, जिसे नीति आयोग के नाम से भी जाना जाता है। जिसे भारत सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में सेवा के लिए बनाया गया है यह संस्थान राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करता है, और भारत सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति पर नजर रखता है। योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी, 2015 को नाम बदल कर नीति आयोग कर दिया गया। यह संस्थान स्वास्थ्य, शिक्षा और उनसे सम्बन्धित विभिन्न नीतियों विभिन्न मुद्दों पर सरकार को सलाह देने के लिए जिम्मेदार है।
- नीति आयोग की प्रशासनिक संरचना :-**
- | | |
|------------------------|---|
| अध्यक्ष | - प्रधानमंत्री |
| उपाध्यक्ष | - प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त |
| संचालन परिषद | - सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केन्द्रशासित राज्यों के उपराज्यपाल |
| क्षेत्रीय परिषद | - विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को सम्बोधित करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा या उसके द्वारा नामित व्यक्ति जो मुख्यमंत्री और उपराज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करता हो। |
| तदर्थ सदस्य | - अग्रणी अनुसंधान संस्थानों से बारी-बारी दो पदेन सदस्य |
| मुख्यकार्यकारी अधिकारी | - भारत सरकार का सचिव जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नामित किया जाता है। |
- 62.** निम्नलिखित में से कौन-सा भारत में सतत् विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है?
- योजना आयोग
 - विनिवेश आयोग
 - नीति आयोग
 - वित्त आयोग
- उत्तर-(c)** UPPCS Pre GS-2019
- व्याख्या –** भारत सरकार कई आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय विकास आधारित क्षेत्र/केन्द्रीय परियोजनाएँ संचालित करती रहती हैं जिन्हें सम्यक् निगरानी तथा क्रियान्वयन की आवश्यकता होती है। ये विकासात्मक कार्यक्रम नीति आयोग द्वारा मूल्यांकित तथा क्रियान्वित किये जाते हैं जो भारत सरकार द्वारा घोषित भारत में सतत् विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है जिसके पास इन सतत् विकास लक्ष्यों को पूर्ण करने हेतु वर्ष 2030 तक की समय सीमा है।

03.

राष्ट्रीय आय

1. हरित सकल राष्ट्रीय आय है—

- (a) कृषि तथा जंगलात की आय का हिस्सा
- (b) विदेशी व्यापार से प्राप्त आय का हिस्सा
- (c) वह हिस्सा जिसमें काला धन नहीं है
- (d) जिसमें पर्यावरण क्षरण का लेखा भी किया गया है

उत्तर-(d) UPPCS (Pre) Economics Opt. 2003

व्याख्या : हरित सकल राष्ट्रीय आय वह आय है जिसमें पर्यावरण क्षरण का भी लेखा किया गया है। अर्थात् राष्ट्रीय आय की गणना करते समय जब पर्यावरण के क्षति को भी राष्ट्रीय आय में सम्मिलित कर लिया जाये तो इसे हरित सकल राष्ट्रीय आय कहते हैं।

2. गिनी गुणांक माप है—

- (a) आय-वितरण की असमानता का
- (b) किसी संयंत्र की पूँजी-तीव्रता का
- (c) कृषि उत्पादन का औद्योगिक उत्पाद से अनुपात का
- (d) द्वितीयक क्षेत्र में रोजगार का तृतीयक क्षेत्र में रोजगार से अनुपात का

उत्तर-(a) UPPCS (Pre) Economics Opt. 2003

व्याख्या : गिनी-गुणांक आय वितरण की असमानता का माप है। गिनी गुणांक का अधिकतम मूल्य 1 के बराबर होगा तथा न्यूनतम मूल्य शून्य के बराबर होगा। यदि G = 0 है तो प्रत्येक व्यक्ति को एक समान आय मिल रही है तथा G = 1 है तो एक ही व्यक्ति पूरी आय प्राप्त कर रहा है। गिनी गुणांक को 1912 में इंटैलियन सांख्यिक केरैडो गिनी ने विकसित किया।

3. निम्नलिखित में से कौन सा एक आय की असमानताओं को नहीं मापता है—

- (a) लॉरेज वक्र
- (b) प्रति व्यक्ति आय
- (c) गिनी गुणांक
- (d) विभिन्न आय वर्गों में जनसंख्या का प्रतिशत

उत्तर-(b) UPPCS (Pre) Economics Opt. 2003

व्याख्या : आय असमानताओं को निम्न मापता है—
 (1) लॉरेज वक्र।
 (2) गिनी गुणांक।
 (3) विभिन्न आय वर्गों में जनसंख्या का प्रतिशत।
 जबकि प्रतिव्यक्ति आय, आय की असमानताओं को नहीं मापता है।

4. सकल-राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है—

- (a) प्रति व्यक्ति उत्पाद
- (b) प्रति व्यक्ति उपभोग
- (c) प्रति व्यक्ति आय
- (d) वास्तविक प्रति व्यक्ति आय

उत्तर-(c) UPPCS (Pre) Economics Opt. 2006

व्याख्या : सकल-राष्ट्रीय आय की कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्रतिव्यक्ति आय प्राप्त होता है।

$$\text{प्रतिव्यक्ति आय} = \frac{\text{सकल राष्ट्रीय आय}}{\text{कुल जनसंख्या}}$$

5. बाजार मूल्यों पर राष्ट्रीय आय बराबर होती है—

- (a) मजदूरी, ब्याज, लगान और हानि की अर्जित राशि
- (b) साधन लागत पर राष्ट्रीय आय तथा परोक्ष करों के जोड़
- (c) सभी साधनों द्वारा अर्जित आय का योग धन (+) प्रत्यक्ष कर छूटन (-) अनुदान
- (d) उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल परिमाण

उत्तर-(b) UPPCS (Pre) Economics Opt. 2002

व्याख्या : बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय साधन लागत पर राष्ट्रीय आय तथा परोक्षकरों के जोड़ के बराबर होती है।

6. निम्न कारण से GNP (सकल राष्ट्रीय उत्पाद) में श्रम की भागीदारी कम है—

- (a) मजदूरी की तुलना में कीमतें कम हैं।
- (b) कीमत की तुलना में लाभ कम है।
- (c) कीमत की तुलना में लाभ कम है।
- (d) कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है।

उत्तर-(d) UPPCS (Mains) G.S. IInd Paper 2008

व्याख्या — कीमतों की तुलना में मजदूरी कम होने के कारण से GNP (सकल राष्ट्रीय उत्पाद) में श्रम की भागीदारी कम है।

7. राष्ट्र की सम्पदा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है?

- | | |
|-------------------|------------|
| (a) खान | (b) बांध |
| (c) मुद्रा-पूर्ति | (d) पशु धन |

उत्तर-(c) UPPCS (Mains) Spl. G.S. IInd 2004

व्याख्या — राष्ट्र की सम्पदा में खान, पशुधन, बांध, बिजली, कृषि आदि शामिल है तथा मुद्रा-पूर्ति शामिल नहीं है।

मुद्रा-पूर्ति से आशय विभिन्न रूपों में उस मुद्रा से है, जो किसी समयावधि में विनियम के लिए उपलब्ध हो।

8. वर्तमान मूल्यों (Current Prices) पर प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income) की वृद्धि दर (Growth Rate) स्थिर मूल्यों (Constant Prices) पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से ध्यान रखा जाता है—

- (a) जनसंख्या वृद्धि की दर का
- (b) मूल्यस्तर की वृद्धि दर का
- (c) मुद्रास्फीति की वृद्धि दर का
- (d) वेतन दर में वृद्धि की दर का

उत्तर-(c) UPPCS (Mains) G.S IInd Paper 2004

UPPCS (Pre) Economics Opt. 2003

व्याख्या — वर्तमान मूल्यों पर प्रतिव्यक्ति आय की वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर प्रतिव्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक होती है, क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रतिव्यक्ति आय की वृद्धि दर में मुद्रा स्फीति की वृद्धि दर का समायोजन किया जाता है।

9. आर्थिक नियोजन के युग में आरम्भ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र हिस्सा—
- निरन्तर कम होता रहा है
 - निरन्तर बढ़ता रहा है
 - पहले बढ़ा फिर कम हुआ है
 - पहले कम होकर फिर बढ़ा है

उत्तर-(c)

UPPCS (Pre.) G.S. 1999

व्याख्या—आर्थिक नियोजन के युग में भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का हिस्सा पहले बढ़ा फिर कम हुआ है—

1950	72.1
1961	79.8%
1971	72.1%
1981	68.7%
1991	33.5%
2001	26.56%
2006	26%
2013–14	18%
2019-20 (RE ^{1st})	18.4%
2020-21 (PE)	20.2%
2021-22 (AE)	18.8%

10. निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है—

- मजदूरी तथा वेतन
- अवकाश पेंशन
- उपदान
- अन्तिम वस्तुएँ

उत्तर-(c) UPPCS (Pre) Economics Opt. 2000

व्याख्या : राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है—

- मजदूरी तथा वेतन।
- अवकाश पेंशन।
- अन्तिम वस्तुएँ।
- सैनिक तथा सुरक्षा सेवायें।
- लाभांश, जो कम्पनियों के ही लाभ के भाग होते हैं।
- भविष्य निधि कोष में मालिकों का अंशदान।
- संसद सदस्य को दिया जाने वाला भत्ता।
- विदेशी पर्यटकों द्वारा भारत में किया गया व्यय।
- मकान मालिकों द्वारा स्व आवास प्रयोग में लाया जाने वाला मकान का किराया।
- ब्रोकर्स कमीशन।

जबकि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित को सम्मिलित नहीं किया जाता—

- हस्तान्तरण भुगतान जैसे—बेरोजगारी भत्ता, पेंशन, जेब खर्च (बच्चों का)।
- पूँजीगत लाभ या हानि, अप्रत्याशित लाभ।
- विदेशों से प्राप्त उपहार।
- एक फर्म द्वारा दूसरी फर्म को दिया जाने वाला लाभांश।
- वित्तीय सौदे।
- एक परिवार या गृहस्थ द्वारा अवकाश में अपने बगीचे में उत्पादित सब्जियां तथा फल, किसी फर्म द्वारा रखे गये स्टॉक की कीमतों में वृद्धि।
- एक फैक्ट्री या बिजली खर्च, वैज्ञानिक खोजों में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएँ, एक होटल द्वारा खरीदी गई सब्जियां तथा अन्य खाद्य, रायल्टी के रूप में किया गया भुगतान इत्यादि।

11. हिन्दू संवृद्धि दर का सम्बन्ध किस संवृद्धि दर से है?

- सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GDP)
- जनसंख्या (Population)
- खाद्यान्न (Food grains)
- प्रतिव्यक्ति आय (Per capita income)

उत्तर-(a)

UPPCS (Pre) G.S. 2006

UPPCS (Mains) G.S IInd 2004

UPPCS (Pre) G.S. 1996

व्याख्या—हिन्दू संवृद्धि दर का संबंध सकल राष्ट्रीय उत्पाद से है। भारत के संदर्भ में विकास की हिन्दू दर का विचार प्रो. राजकृष्णा ने वर्ष 1981 में दिया। प्रो. राजकृष्णा का मानना था कि भारतीय अर्थव्यवस्था निम्न आर्थिक संवृद्धि के संतुलन जाल में उलझ कर रह गयी, जो 3.5% प्रतिवर्ष की संवृद्धि दर थी। अर्थव्यवस्था की अन्तर्निहित अपरिवर्तीयता का यह सूचक हिन्दू जीवन शैली के ही समान थी। प्रो. राजकृष्णा का यह विश्लेषण स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम तीन दशकों की संवृद्धि दरों पर आधारित था जो कि वर्ष 1950–1980 बीच औसतन 3.5% था।

12. ‘वास्तविक राष्ट्रीय आय’ में वृद्धि होती है, जबकि—

- आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं
- लोगों की बचतें बढ़ जाती हैं
- अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है
- अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन बढ़ जाता है

उत्तर-(d) UPPCS (Pre) Economics Opt. 1999

व्याख्या : ‘वास्तविक राष्ट्रीय आय’ में वृद्धि तब होती है जबकि अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन बढ़ जाता है।

13. इस समय (2015) से भारत की राष्ट्रीय आय के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष आधार वर्ष के रूप में प्रयुक्त हो रहा है?

- 2004–05
- 2001–02
- 2011–12
- 2007–08

उत्तर-(c) UPPCS (Mains) G.S. Ist 2016

व्याख्या—इस समय (2015 से) भारत की राष्ट्रीय आय के अनुमान हेतु 2011–12 आधार वर्ष के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। आर्थिक सूचकांक बनाते समय मूल्यों की तुलना के लिए किसी वर्ष विशेष के मूल्यों को आधार बनाया जाता है। इस वर्ष विशेष को ही आधार वर्ष कहा जाता है। इस आधार वर्ष के मूल्यों को 100 मानकर अन्य वर्षों के मूल्यों को परिवर्तित किया जाता है ताकि एक स्तर पर तुलना हो सके।

14. शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन (NNP) बराबर होता है—

- GNP—सकल कर
- GNP—विदेशी सहायता
- GNP—पूँजी हास
- GNP—अप्रत्यक्ष कर

उत्तर-(c) UPPCS (Pre) Economics Opt. 1999

व्याख्या : शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP) ज्ञात करने के लिए GNP में से पूँजी स्टॉक की खपत या मूल्य (पूँजी) हास को घटा देते हैं। अर्थात्—

NNP = GNP – Depreciation
या, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद = GNP – मूल्य (पूँजी) हास।

15. भारतवर्ष की राष्ट्रीय आय का अनुमान, निम्नलिखित में से, सर्वप्रथम किसने लगाया था—

- के.एन. राज
- वी.के.आर.वी. राव
- दादा भाई नौरोजी
- पी.सी. महालनोबिस

उत्तर-(c) UPPCS (Pre) Economics Opt. 1999, 2001

व्याख्या : भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम वर्ष 1868 में दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक ‘पावर्टी एण्ड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया’ में इस सम्बन्ध में बताया। उस समय राष्ट्रीय आय का अनुमान लगभग 340 करोड़ रुपया लगाया गया जबकि प्रतिव्यक्ति आय 20 रुपया मासिक थी। वर्तमान में राष्ट्रीय आय का अनुमान NSO (राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय) द्वारा लगाया जा रहा है।

16. भारत में कौन सा क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है-

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| (a) घरेलू क्षेत्र | (b) निगम क्षेत्र |
| (c) सार्वजनिक क्षेत्र | (d) सहकारी क्षेत्र |

उत्तर-(a) **UPPCS (Pre) Economics Opt. 2000**
UPPCS (Pre.) G.S. 2003
UPPCS (Mains) G.S IInd Paper 2004

व्याख्या : भारत में घरेलू क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है।

आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2019-20 के दौरान भारत में घरेलू क्षेत्र का योगदान सकल घरेलू बचत में 19.6 प्रतिशत है।

17. राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना का परिहार किया जाता है।

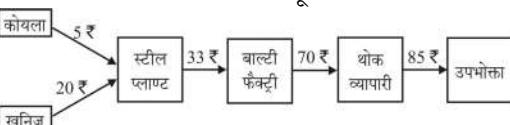
- | |
|---|
| (a) वित्तीय अन्तरणों को अलग करके |
| (b) सकल राष्ट्रीय उत्पाद की माप के लिये वर्धित मूल्य विधि का उपयोग करके |
| (c) पहले से उत्पादित वस्तुओं के बाजार मूल्य को अलग करके |
| (d) उन वस्तुओं को छोड़ देने से जो कि बाजार विनियोग में नहीं आती है |

उत्तर-(b) **UPPCS (Pre) Economics Opt. 1994**

व्याख्या : राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना का परिहार सकल राष्ट्रीय उत्पाद की माप के लिए वर्धित मूल्य विधि का प्रयोग करके किया जाता है। मूल्य वर्धित विधि के अनुसार उत्पादन से उपभोग तक की शृंखला में प्रत्येक उत्पादक इकाई कच्चे माल या आगत में जिसे वह दूसरे से प्राप्त करती है, कुछ उत्पादन किया या सेवा जोड़ती है और इसे वह दूसरी कड़ी को नये मूल्य के साथ जोड़ देती है। जिस मूल्य पर उसने आगत को दूसरे से प्राप्त किया और जिस रूप में उसने अगली कड़ी को सामान के रूप में दिया, इन दोनों का अन्तर ही उस उत्पादक इकाई द्वारा वर्धित मूल्य है, और प्रत्येक इकाई द्वारा इस प्रकार से किए गये वर्धित मूल्यों का योग ही सकल उत्पाद का मूल्य है।

इसको निम्न उदाहरण से समझा जा सकता है-

लोहे के बाल्टी निर्माण की प्रक्रिया में मूल्य वर्धित विधि –



18. निम्न राज्यों में से किस एक की प्रति व्यक्ति चालू कीमतों पर आय, वर्ष 2004-05 में सबसे कम थी?

- | | |
|------------|------------------|
| (a) असम | (b) बिहार |
| (c) उड़ीसा | (d) उत्तर प्रदेश |

उत्तर-(b) **UPPCS (Pre) Economics Opt. 2009**
UPPCS (Pre) G.S. 2008, 1993
UPLower (Pre) G.S. 2003-04

व्याख्या— प्रश्नकाल के दौरान एवं वर्तमान में भी चालू कीमतों पर सबसे कम प्रतिव्यक्ति आय बिहार की है। वर्तमान में सर्वाधिक राज्य प्रतिव्यक्ति आय चालू कीमतों में भारत के सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में गोवा (435959 रु.) की है।

आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार, वर्ष 2019-20 की अवधि में दिए गए राज्यों में वर्तमान मूल्यों पर प्रतिव्यक्ति आय जिसे प्रतिव्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद से मापा जाता है, निम्नवत रही :

राज्य	प्रतिव्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद (2019-20)
उड़ीसा	110434 ₹
असम	86801 ₹
उत्तर प्रदेश	65704 ₹
बिहार	45071 ₹

19. राष्ट्रीय आय का सामान्य रूप से अर्थ है:

- | |
|---|
| (a) बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद |
| (b) बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद |
| (c) साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद |
| (d) साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद |

उत्तर-(d) **UPPCS (Pre) Economics Opt. 1996**
IAS (Pre) G.S. 1997

व्याख्या : राष्ट्रीय आय का सामान्य रूप से अर्थ है : साधन लागत पर निवल/शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP_{FC})।

राष्ट्रीय आय = NNP_{FC} = GNP_{MP} - मूल्य हास - परोक्षकर + सब्सिडी

20. GNP और GDP में अन्तर है :

- | |
|---------------------------------|
| (a) सकल विदेशी विनियोग का |
| (b) शुद्ध विदेशी विनियोग का |
| (c) शुद्ध निर्यात का |
| (d) विदेशों से शुद्ध साधन आय का |

उत्तर-(d) **UPPCS (Pre) Economics Opt. 1996, 2001**

व्याख्या : GNP और GDP में मुख्य अंतर विदेशों से प्राप्त शुद्ध/निवल साधन आय का होता है। GDP -किसी देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग होता है। इसके अंतर्गत निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा किए गए उत्पादन को शामिल किया जाता है, चाहे उत्पादन स्थानीय निवासियों/कर्मचारियों द्वारा किया गया हो या विदेशी।

GNP से आशय एक देश के सभी उत्पादन के साधनों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य से है। GNP में एक देश के सभी नागरिकों द्वारा उत्पादित आर्थिक उत्पादन को शामिल किया जाता है। चाहे वे नागरिक राष्ट्रीय सीमा में कार्यरत हों या विदेशों में। इसे निम्न रूप से व्यक्त किया जाता है।

GNP_{MP} = GDP_{MP} + विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय

21. सकल राष्ट्रीय उत्पाद एवं सकल घरेलू उत्पाद का अन्तर बाबर है-

- | |
|--|
| (a) विदेशों से प्राप्त संसाधान आय |
| (b) शुद्ध विदेशी निवेश |
| (c) विदेशी से प्राप्त शुद्ध संपत्ति/आय |
| (d) सकल विदेशी निवेश |

उत्तर-(c) **UP PSC ACF/RFO (Mains) 2019 Paper II**

व्याख्या— उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

22. राष्ट्रीय आय समिति की नियुक्ति कब हुई—
 (a) 1949 (b) 1950
 (c) 1951 (d) 1952

उत्तर-(a) UPPCS (Pre) Economics Opt. 1997

व्याख्या : 1949 ई. में पी.सी. महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। डी.आर. गाडगिल एवं वी.के.आर.वी. राव इसके सदस्य थे। प्रो. साइमन कुजनेट्स इसके सलाहकार थे। समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट 1951 में तथा अंतिम रिपोर्ट 1954 में दी।

23. राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे—
 (a) जवाहर लाल नेहरू (b) महालनोबिस
 (c) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर-(b) UPPCS (Pre) Economics Opt. 1991

व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

24. सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) बराबर होता है—
 (a) प्रयोज्य आय
 (b) शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद + घिसावट
 (c) सकल राष्ट्रीय उत्पाद + घिसावट व्यय
 (d) सकल घरेलू उत्पाद + प्रत्यक्ष कर

उत्तर-(b) UPPCS (Pre) Economics Opt. 1993

व्याख्या : यदि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP) में पूँजी स्टॉक की खपत या मूल्यहास को जोड़ दिया जाये तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होगा।

$$\text{GNP} = \text{NNP} + \text{Depreciation}$$

सकल राष्ट्रीय उत्पाद में एक देश के सभी नागरिकों द्वारा उत्पादित आर्थिक उत्पादन को शामिल किया जाता है, चाहे वे नागरिक राष्ट्रीय सीमा के भीतर स्थापित हों या विदेश में।

25. राष्ट्रीय आय की गणना होती है—
 (a) प्रचलित कीमतों पर
 (b) प्रचलित एवं स्थिर दोनों कीमतों पर
 (c) स्थिर कीमतों पर
 (d) मूल्यानुपातों पर

उत्तर-(b) UPPCS (Pre) Economics Opt. 1992

व्याख्या : राष्ट्रीय आय की गणना प्रचलित एवं स्थिर दोनों कीमतों पर होती है। चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय की गणना के अन्तर्गत एक दिये गये वर्ष के उत्पादों को उसी वर्ष की कीमतों के आधार पर मापा जाता है। इस माप में कीमतों के उत्तर-चढ़ाव सम्मिलित रहते हैं, जिससे यह राष्ट्रीय आय की वास्तविक माप नहीं करता है।

स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना एक दिये गये वर्ष के उत्पादों की माप आधार वर्ष की कीमतों पर की जाती है। आधार वर्ष की कीमतों को आधार वर्ष के लिए तथा साथ ही उसके पश्चात् अन्य वर्षों के लिए स्थिर मान लिया जाता है। अतः यह कीमतों के उत्तर-चढ़ाव को दूर कर देता है, इसीलिए यह आय में होने वाली वास्तविक परिवर्तन को व्यक्त करता है।

26. भारत में राष्ट्रीय आय का आगणन कौन-सा संस्थान करता है?
 (a) आर. बी. आइ. (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया)
 (b) सी. एस. ओ. (केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन)

- (c) एन. एस. एस. ओ. (राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन)
 (d) आइ. एस. आइ. (भारतीय सांख्यिकी संस्थान)

उत्तर-(b) UPPCS ACF (Mains)-2017

UPPCS (Pre) Economics Opt. 1993

1994, 1995, 2000, 2006

UPPCS (Mains) G.S. Ist Paper 2008, 2010

UP Lower (Pre.) G.S. 2004

UPPCS Tax Inspector-2003

U.P. PCS Medical Officer 2018

व्याख्या : प्रश्नकाल में भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (CSO) द्वारा किया जाता था, जिसकी स्थापना 2 मई, 1951 को की गई थी। यद्यपि इसका प्रारम्भ 1949 में एक सांख्यिकीय इकाई के रूप में किया गया था। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा किया जा रहा है।

27. निम्न कारणों से कौन कारण भारत के प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में धीमी बढ़त के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी रहा?

1. जनसंख्या में तेज वृद्धि।
2. मूल्यों में भारी बढ़त।
3. कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में धीमी गति।
4. विदेशी विनियम की अनुपलब्धता।

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए-

- | | |
|-------------|-----------------|
| (a) 1 एवं 2 | (b) 1, 2 एवं 3 |
| (c) 1 एवं 4 | (d) उपरोक्त सभी |

उत्तर-(b) UPPCS (Pre.) G.S. 2001

व्याख्या : प्रति व्यक्ति वास्तविक आय के धीमी बढ़त के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी रहा है—(i) जनसंख्या में तेज वृद्धि, (ii) कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में धीमी गति, (iii) बेरोजगारी में वृद्धि।

28. भारत में निम्नलिखित चार प्रमुख क्षेत्रों से बचत का उदय होता है—

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 1. गृहस्थ | 2. निजी निगम क्षेत्र |
| 3. सार्वजनिक निगम एवं अन्य लोक उपक्रम | 4. सरकार |

नीचे दिये कूट का उपयोग करते हुए उपर्युक्त क्षेत्रों के योगदान का सही अवरोही क्रम इंगित कीजिये—

कूट :

- | | |
|-------------------|------------------|
| (a) 4, 3, 2 और 1 | (b) 1, 3, 2 और 4 |
| (c) 1, 2, 3, और 4 | (d) 4, 2, 3 और 1 |

उत्तर-(c) UP Lower (Pre.) G.S. 1998

व्याख्या : प्रश्नकाल के दौरान, भारत में सकल घरेलू बचत में उपर्युक्त क्षेत्रों के योगदान का अवरोही क्रम है—गृहस्थ क्षेत्र, निजी निगम क्षेत्र, सार्वजनिक निगम एवं अन्य लोक उपक्रम तथा सरकारी क्षेत्र हैं।

आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2019-20 में सकल घरेलू बचत में निम्न क्षेत्रों का योगदान इस प्रकार है—

घरेलू क्षेत्र	19.6%
निजी निगम क्षेत्र	10.7%
सार्वजनिक क्षेत्र	1.1%
कुल	31.4%

1. कृषि उत्पाद (विकास एवं मालगोदाम निगम) अधिनियम पास हुआ था
 (a) 1956 (b) 1966
 (c) 1976 (d) 1986

UPPSC Unani Medical Officer-2018

Ans. (a) : कृषि उत्पाद (विकास एवं मालगोदाम निगम) अधिनियम 1956 में पारित हुआ।

2. उत्तर प्रदेश में 'कृषक समृद्धि आयोग' की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी?
 (a) 2016 (b) 2017
 (c) 2018 (d) None of the above

UPPSC RO/ARO (Mains) 2021

Ans. (b) : उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना नवंबर 2017 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में की गई थी। कृषक समृद्धि आयोग का उद्देश्य वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगनी करना है।

3. भारत सरकार ने 'प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेरायटीज एण्ड फार्मर्स राइट अधिनियम' निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया?
 (a) 2001 (b) 2005
 (c) 2015 (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

UPPSC RO/ARO (Mains) 2021

Ans. (a) : भारत सरकार ने, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेरायटीज एण्ड फार्मर्स राइट अधिनियम, को वर्ष 2001 में पारित किया। इससे पौधों की किस्म, कृषकों और पौधों के संवर्धकों, के अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रभावी प्रणाली स्थापित करने तथा पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करने हेतु लाया गया था।

4. भारत के कृषि उत्पाद, व्यापार व वाणिज्य बिल 2020 में से निम्न में किसका उल्लेख नहीं किया गया है?
 (a) आवश्यक वस्तुएँ
 (b) संविदा कृषि
 (c) न्यूनतम समर्थन मूल्य
 (d) कृषि उत्पादन विपणन समितियाँ

UPPSC RO/ARO (Pre) 2021

Ans. (c) : भारत के कृषि उत्पाद, व्यापार व वाणिज्य बिल 2020 में आवश्यक वस्तुएँ, संविदा कृषि एवं कृषि उत्पादन विपणन समितियों का उल्लेख है जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य का उल्लेख नहीं किया गया है।

सितम्बर, 2020 में किसानों के हित के लिए तीन विधेयक पारित किए गए-

- किसान उपज, व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक – 2020
- मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) अनुबंध विधेयक – 2020
- आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक – 2020

5. भारत में कृषि क्षेत्र में छूटों (फार्म सब्सिडी) के सन्दर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए।

- भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरकों पर दी जाने वाली, अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अन्तर्गत आती है।
- किसानों को बिजली एवं सिंचाई पर दी जाने वाली कटौतियाँ प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अन्तर्गत आती हैं।
- विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटी.ओ.) के कृषि सम्बन्धी प्रावधान प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी की अनुमति देते हैं, परन्तु अप्रत्यक्ष सब्सिडी पर रोक लगाते हैं।
- भारत में सरकारों द्वारा दी जाने वाली सभी सब्सिडियाँ अप्रत्यक्ष श्रेणी में आती हैं।

नीचे दिये गये कूट की सहायता से सही कथन का चयन कीजिये।

कूट:

- | | |
|-------------|-------------|
| (a) 1 तथा 2 | (b) 3 तथा 4 |
| (c) 2 तथा 3 | (d) 1 तथा 4 |

UPPSC (Pre) 2022

Ans. (*) : भारत में कृषि क्षेत्र के विकास एवं प्रोत्साहन के लिए कृषि क्षेत्र में छूटें (फार्म सब्सिडी) प्रदान की जाती है। यह दो प्रकार की होती है- प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी और अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी। अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत सिंचाई, बिजली, खाद, ऋण, और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दी जाने वाली सब्सिडियां आती हैं। प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत ऐसी सब्सिडियां आती हैं जो सीधे किसानों को नगद सहायता के रूप में प्रदान की जाती हैं, जैसे - एल.पी.जी. सिलेण्डर पर सब्सिडी आदि में दी जाने वाली सहायता। अतः कथन (1) सत्य है; कथन (2) और कथन (4) असत्य है। विश्व व्यापार संगठन (WTO) के कृषि संबंधी ग्रीन बॉक्स प्रावधान फार्म सब्सिडी की सीमित मात्रा में अनुमति देते हैं परन्तु ऐसी किसी प्रत्यक्ष सब्सिडी पर रोक लगाते हैं जो व्यापार को प्रभावित करने

वाली हो और यह सरकार द्वारा ही प्रदान की गई हो तथा इसमें कीमत समर्थन शामिल न हो। डब्लू टी ओ के कृषि संबंधी घरेलू समर्थन प्रावधान के अंतर्गत तीन बॉक्स के रंगों नीला, हरा और एम्बर के आधार पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। विकासशील देशों के लिए R&D box (डैवेलपमेंट बॉक्स) के तहत छूट प्राप्त है।

अतः कथन (3) असत्य है।

नोट- आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर **(d)** माना है।

6. ऐगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया?

- | | |
|--------------|--------------|
| (a) 1937 में | (b) 1952 में |
| (c) 1957 में | (d) 1965 में |

उत्तर-(a)

UPPCS (Mains) G.S. Ist 2009

व्याख्या—ऐगमार्क एक्ट कृषि उत्पादन से संबंधित है जो 1937 में बनाया गया था जिसमें उत्पादन की मानक गुणवत्ता और मूल्यांकन इस एक्ट के तहत की जाती है तब उत्पादक समूह को यह मार्क प्रदान किया जाता है।

7. कृषि विस्तार का प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रणाली (training & visit system) अपनाने वाला प्रथम राज्य था—

- | | |
|--------------|-------------------|
| (a) राजस्थान | (b) उत्तर प्रदेश |
| (c) पंजाब | (d) आन्ध्र प्रदेश |

उत्तर-(a)

UPPCS (Mains) G.S. Ist 2015

व्याख्या—कृषि विस्तार का प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रणाली (Training and Visit System) वर्ल्ड बैंक के विशेषज्ञ डेनियल बेनर द्वारा विकसित की गई थी। भारत में सर्वप्रथम 1974 में राजस्थान कैनाल क्षेत्र एवं मध्य प्रदेश के चम्बल कमांड एरिया में इस विस्तार कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वर्तमान में कुल 13 राज्यों में यह प्रणाली प्रचलित है।

8. निम्नलिखित में से कौन कृषि वित्त का प्रमुख सिद्धान्त है?

- | | |
|----------------------|-----------------|
| (a) उद्देश्य | (b) व्यक्ति |
| (c) उत्पादकता नियोजन | (d) उपरोक्त सभी |

उत्तर-(d) **UPPCS (Mains) G.S. Ist Paper, 2016**

व्याख्या— कृषि वित्त, ग्रामीण विकास एवं कृषि से संबंधित गतिविधियों से जुड़े कार्यों के सम्पादन से संबंधित ऐसी वित्त व्यवस्था है जो उसके आपूर्ति, थोक, वितरण, प्रसंस्करण और विपणन के वित्त पोषण के लिए समर्पित एक विभाग के रूप में जाना जाता है। किसानों की ऋण आवश्यकताओं को निम्नलिखित तथ्यों के आधार निर्धारित किया जा सकता है—

(1) समय के आधार पर- लघु अवधि, मध्यम अवधि और लम्बे समय तक की अवधि के लिए ऋण।

(2) उद्देश्य के आधार पर- उत्पादक आवश्यकता, खपत की जरूरत और अनुत्पादक आवश्यकता।

9. भारत सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय लिया है—

- (a) गन्ना उत्पादकों के लिए
- (b) कॉफी व चाय उत्पादकों के लिए
- (c) आलू व प्याज उत्पादकों के लिए
- (d) टमाटर उत्पादकों के लिए

उत्तर-(b) **UPPCS (Pre) G.S. Spl. 2004**

व्याख्या— भारत सरकार ने 2004 में कॉफी, चाय, रबड़ आदि बागानी तथा व्यापारिक फसलों के मूल्यों को स्थिर रखने के लिए कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय लिया है।

10. निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कृषि तथा सम्बद्धि क्षेत्रों को सर्वाधिक साख प्रदान करती है?

- (a) सहकारी बैंक
- (b) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- (c) वाणिज्यिक बैंक
- (d) संयुक्त रूप से सहकारी तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

उत्तर-(c) **UPPCS (Pre) GS, 2010**

व्याख्या—भारत में सर्वाधिक कृषि साख वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया जाता रहा है।

11. कथन (A) : सरकार के बजट में घाटे का एक बड़ा स्रोत अर्थ साहाय्य है।

कारण (R) : भारतीय कृषि में विकसित देशों की तुलना में अर्थ साहाय्यों का स्तर बहुत अधिक है।

सही उत्तर का चयन नीचे दिये गये कूट की सहायता से कीजिए।

कूट :

- (a) A तथा R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है
- (b) A तथा R दोनों सही हैं परन्तु R, A की सही व्याख्या नहीं है
- (c) A सही है परन्तु R गलत है
- (d) A गलत है परन्तु R सही है

उत्तर-(c) **UPPCS (Mains) G.S. Ist 2002**

व्याख्या—बजट में भारत सरकार के व्यय को दो भागों में बाँटा जा सकता है (1) राजस्व व्यय, (2) पूँजीगत व्यय। राजस्व व्यय को भी दो भागों में बाँटा जा सकता है—(i) विकासात्मक व्यय, (2) गैर विकासात्मक व्यय। बजट 2022-23 के अनुसार व्यय का वर्गीकरण निम्न है—ब्याज 20%, करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 17% केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएँ 9% रक्षा 8% अर्थिक सहायता 8% आदि। अर्थिक सहायता (Subsidies) के सबसे ज्यादा खाद्य सहायता आती है। उसके पश्चात क्रमशः ऊर्वरक, पेट्रोलियम आदि। अतः स्पष्ट है। भारत में कृषि में अर्थ साहज्य अधिक नहीं है।

<p>12. भारतीय कृषि के लिए निम्न में से कौन सा संस्थागत साख का स्रोत नहीं है?</p> <p>(a) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (b) साहूकार (c) सहकारी समितियाँ (d) वाणिज्यक बैंक</p> <p>उत्तर-(d) UPPCS (Pre) Economics Opt. 2004, 1994</p>	<p>व्याख्या- कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों को सर्वाधिक साख वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राप्त होती है।</p>
<p>13. कृषि उत्पाद (विकास एवं मालगोदाम निगम) अधिनियम पास हुआ था</p> <p>(a) 1956 (b) 1966 (c) 1976 (d) 1986</p> <p>उत्तर-(a) UPPSC Unani Medical Officer-2018</p>	<p>व्याख्या : भारतीय कृषि के लिए साहूकार संस्थागत साख का स्रोत नहीं है। जबकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी समितियाँ तथा वाणिज्यक बैंक आदि भारतीय कृषि के लिए संस्थागत साख का स्रोत है। RBI की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 की अवधि में सर्वाधिक कृषि साख वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया गया।</p>
<p>14. निम्न कथन से हम क्या समझते हैं?</p> <p>“भारत ने राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त कर ली है, परन्तु पारिवारिक सुरक्षा नहीं प्राप्त की है?”</p> <p>(a) प्रत्येक परिवार को अन्तःस्थ “बफर” स्टॉक उपलब्ध नहीं है (b) खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि दर्शाता है परन्तु प्रति व्यक्ति उपलब्धता घटी है (c) गरीबी से नीचे रेखा में व्यक्तियों की संख्या बढ़ी है (d) खाद्यान्न स्टॉक पर्याप्त है परन्तु सभी परिवारों को उसे प्राप्त करने की सामर्थ्य नहीं है</p> <p>उत्तर-(d) UPPCS (Mains) Spl. G.S. IInd 2008</p>	<p>व्याख्या- कृषि उत्पाद (विकास एवं मालगोदाम निगम) अधिनियम 1956 में पारित हुआ।</p>
<p>15. भारत में निम्नलिखित में से किस की कृषि तथा सहबद्ध गतिविधियों में ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी है?</p> <p>(a) वाणिज्यिक बैंकों की (b) सहकारी बैंकों की (c) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की (d) सूक्ष्म-वित्त (माइक्रोफाइनेंस) संस्थाओं की</p> <p>उत्तर-(a) UPPCS (Mains) G.S. IInd Paper 2010 UPPCS (Mains) G.S. IInd 2006</p>	<p>व्याख्या- निम्नलिखित में से किस की कृषि तथा सहबद्ध गतिविधियों में ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी है?</p> <p>(a) साहूकार (b) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (c) सहकारी बैंक (d) व्यापारिक बैंक</p> <p>उत्तर-(a) UPPCS (Pre) Economics Opt. 2005</p>
<p>16. भारतीय कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत साख का स्रोत नहीं है?</p> <p>(a) साहूकार (b) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (c) सहकारी बैंक (d) व्यापारिक बैंक</p> <p>उत्तर-(a) UPPCS (Pre) Economics Opt. 2005</p>	<p>व्याख्या : भारतीय कृषि के लिए साहूकार संस्थागत साख का स्रोत नहीं है। जबकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी समितियाँ तथा वाणिज्यिक बैंक आदि भारतीय कृषि के लिए संस्थागत साख का स्रोत है। RBI की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 की अवधि में सर्वाधिक कृषि साख वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया गया।</p>
<p>17. न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है –</p> <p>(a) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (b) राज्य सरकार (c) कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (d) इनमें से कोई नहीं</p> <p>उत्तर-(c) UPPCS Spl. (Pre) G.S. 2008</p>	<p>व्याख्या- न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य दर है, जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेची जाने वाली अनाज की पूरी मात्रा क्रय करने के लिए तैयार हो। प्रमुख कृषि वस्तुओं के सम्बन्ध में वसूली मूल्य या न्यूनतम समर्थित मूल्य की घोषणा सरकार वर्ष में दो बार रबी और खरीफ के मौसम में करती है। वसूली या न्यूनतम मूल्य की घोषणा सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की संस्तुति पर करती है।</p>
<p>18. मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है,</p> <p>(a) परिसीमन मूल्य (b) बाजार मूल्य (c) न्यूनतम समर्थन मूल्य (d) उपार्जन मूल्य</p> <p>उत्तर-(c) UPPCS (Mains) Spl. G.S. Ist 2008</p>	<p>व्याख्या- वर्तमान में आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कि सिफारिस पर 22 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा गन्ना का उचित एवं लाभकारी मूल्य (कुल 23 फसल) की घोषणा रबी एवं खरीफ की फसलों की बुआई के पूर्व करती है। 1970 के मध्य तक सरकार इन फसलों के दो मूल्यों अर्थात् न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) एवं खरीद मूल्य (Procurement Prices) की घोषणा क्रमशः फसल बुआई के पूर्व एवं कटाई के पश्चात करती थी। जिसमें खरीद मूल्य का मान सामान्यतः खुले बाजार मूल्य से कम एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक होता था। अतः वर्तमान में सरकार खाद्यान्न फसलों को किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय करती है।</p>
<p>19. निम्न में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण सम्बन्धी संस्तुति करता है?</p> <p>(a) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (b) नाबांड</p>	<p>व्याख्या- निम्न में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण सम्बन्धी संस्तुति करता है?</p> <p>(a) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (b) नाबांड</p>

- (c) कृषि लागत एवं कीमत आयोग
(d) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान

उत्तर-(c)

UPPCS (Pre.) Re-exam. 2015

व्याख्या – कृषि लागत एवं कीमत आयोग फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण सम्बन्धी संस्तुति करता है। उल्लेखनीय है कि 1965 में कृषि मूल्य आयोग (APC) की स्थापना हुई थी जिसके अध्यक्ष प्रो. एम. एल. दाँतवाला थे। 1985 में दिया गया CACP इसी का नया नाम है। मूल्य के सम्बन्ध में अपनी संस्तुतियां देते समय आयोग निम्न बातों पर ध्यान रखता है –
(i) आगत को लागत में परिवर्तन, (ii) अन्तर फसल मूल्य समता, (iii) मांग पूर्ति अन्तराल, (iv) मूल्य स्थिति, (v) वैशिक उपलब्धता, (vi) कृषि तथा गैर कृषि क्षेत्र के बीच व्यापार।

20. भारत में व्यावसायिक फसलों के लिए मूल्य समर्थित अभियान के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय नोडल एजेन्सी है-

- (a) एफ.सी.आई. (b) नाबार्ड
(c) ट्राइफेड (d) ट्रिफेड

उत्तर-(c)

UPPCS ACF (Mains)-2017

व्याख्या– कृषि उपजों के विपणन कार्य हेतु सहकारी क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (NAFED) की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 में की गई थी। उल्लेखनीय है कि नेफेड, व्यावसायिक फसलों के लिए मूल्य समर्थित अभियान के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय नोडल एजेन्सी है।

ट्राइफेड (TRIFED) : जनजातीय लोगों का शोषण करने वाले निजी व्यापारियों से छुटकारा दिलाने और इनके द्वारा तैयार की गई वस्तुओं का अच्छा मूल्य दिलाने के उद्देश्य से सरकार ने अगस्त, 1987 में भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ की स्थापना की थी। उल्लेखनीय है कि 12 जुलाई, 1982 को कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड की स्थापना शिवरामन कमेटी की संस्तुति पर हुई थी। इसका मुख्यालय मुम्बई में है।

21. सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाये रखने के लिए बफर स्टाक के निर्माण के लिए सरकार जिस मूल्य पर अनाज खरीदती है, उसे क्या कहा जाता है?

- (a) न्यूनतम समर्थन मूल्य (b) खरीद मूल्य
(c) जारी मूल्य (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर-(a)

UP PSC Vetting Officer 2020

व्याख्या–किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने तथा अत्यधिक खाद्यान उत्पादन होने पर फसलों के मूल्य को स्थिर बनाये रखने के लिए भारत सरकार कृषि एवं लागत मूल्य आयोग की

अनुशंसा पर 22 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा गत्रे का उचित एवं लाभकारी मूल्य (कुल 23 फसल) की घोषणा फसल की बुआई के पूर्व करती है। 1970 के दशक मध्य तक सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा खरीद मूल्यों (Procurement Prices) की घोषणा करती थी। खरीद मूल्य की घोषणा फसल कटाई के पश्चात की जाती थी और जिसका मूल्य सामान्यतः न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से से ज्यादा तथा बाजार मूल्य से कम होता था। अतः उस समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने के लिए सरकारी एजेंसीओं एवं FCI द्वारा खाद्यानों का क्रय खरीद मूल्यों पर किया जाता था। वर्तमान में अर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा 23 फसलों का केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की घोषणा फसल बुआई के पूर्व की जाती है।

22. कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई, वर्ष-

- (a) 1955 में (b) 1965 में
(c) 1970 में (d) 1973 में

उत्तर-(b)

UPPCS (Mains) G.S. Ist 2002

व्याख्या–सन् 1965 ई. में कृषि कीमत आयोग (CAP) का गठन, कृषि उपजों के समर्थन मूल्य निर्धारण हेतु किया गया, जिसने सर्वप्रथम गेहूँ के संदर्भ में न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की। सन् 1985 ई. में इस कमीशन का नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) कर दिया गया।

23. कृषि पैदावार के न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. यदि बाजार मूल्य अधिक है, तो किसान अपनी पैदावार सरकार को बेचेंगे।
2. यह किसानों की पैदावार के लिए न्यूनतम निश्चित मूल्य सुनिश्चित करता है।
3. यह खाद्य सुरक्षा मिशन में सहायक है।
4. यह किसानों के लिए अत्यधिक लाभदायक है क्योंकि वे अपनी पैदावार पर अत्यधिक लाभ कमाते हैं।

उपर्युक्त में से सही कथन हैं-

- (a) केवल 2 तथा 3 (b) केवल 1, 2 तथा 4
(c) केवल 2, 3 तथा 4 (d) केवल 1, 2 तथा 3

उत्तर-(a)

UPPCS ACF (Mains)-2017

व्याख्या–न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा कृषि उत्पादकों को कृषि उत्पादों के मूल्यों में किसी तीव्र गिरावट के विरुद्ध सुरक्षित किए जाने वाले बाजार हस्तक्षेप का एक मुख्य रूप है। भारत सरकार द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की अनुशंसाओं के आधार पर 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। वर्तमान में यह खाद्य सुरक्षा मिशन में भी सहायक सिद्ध हुआ है।

05.

उद्योग क्षेत्र

1. भारत में औद्योगिक विकास हेतु 'संयुक्त क्षेत्र' का विचार किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव में रखा गया?

- (a) 1948 की औद्योगिक नीति में
- (b) 1956 की औद्योगिक नीति में
- (c) 1980 की औद्योगिक नीति में
- (d) 1991 की औद्योगिक नीति में

उत्तर-(b) UPPCS (Mains) Spl. G.S. IInd 2004

व्याख्या— भारत की दूसरी औद्योगिक नीति (1956) में 'संयुक्त क्षेत्र' की संकल्पना रखी गयी। जिसके अनुसार औद्योगिकीकरण में तीव्रता लाने हेतु सार्वजनिक एवं सहकारी क्षेत्र के साथ-साथ विकास पर जोर दिया गया।

2. वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति के अनुसार कितने उद्योगों को लाइसेंसिंग के अन्तर्गत रखा गया था?

- | | |
|--------|--------|
| (a) 6 | (b) 10 |
| (c) 14 | (d) 18 |

उत्तर-(d) UPPCS (Mains) Spl. G.S. IInd 2004

व्याख्या— तत्कालीन पी.वी. नरसिंह राव सरकार ने 24 जुलाई, 1991 को एक नई औद्योगिक नीति की घोषणा की जिसमें बहुत से उदारवादी कदम उठाए गए। इसके तहत लाइसेंसिंग व्यवस्था को लगभग समाप्त कर दिया गया तथा बहुत से आरक्षित उद्योगों के द्वारा निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया। इस औद्योगिक नीति के अन्तर्गत मात्र 18 उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था बनाई गई। ज्ञातव्य है कि उस समय तत्कालीन वित्तमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी थे। वर्तमान में केवल 5 उद्योग ही लाइसेंसिंग नीति के अधीन हैं।

3. भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा का वर्ष था :

- | | |
|----------|----------|
| (a) 1990 | (b) 1991 |
| (c) 1992 | (d) 1988 |

उत्तर-(b) UPPCS (Pre) Economics Opt. 1996

व्याख्या :— नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत निम्नलिखित कदम उठाये गये—,

1. औद्योगिक लाइसेंसिंग
2. एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार (MRTP)
3. सार्वजनिक क्षेत्र
4. विदेशी निवेश
5. विदेशी प्रोटोकॉलों के सम्बन्ध में नीतिगत निर्णयों की घोषणा की गयी।
4. निम्न केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में से कौन दस उच्चतम लाभकारी उद्यमों में सम्मिलित नहीं है (2008)?

- (a) भारत संचार निगम लि.
- (b) राष्ट्रीय टेक्स्टाइल कारपोरेशन लि.
- (c) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि.
- (d) गेल (इण्डिया) लि.

उत्तर-(b) UPPSC AE-2007 II

व्याख्या— प्रश्नकाल के समय भारतीय संचार निगम लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी संचार कंपनी थी 24% बाजार पूँजी संचार क्षेत्र की हिस्सेदारी इसके पास थी उस समय इसके पास मिनी रत्न का दर्जा था। वर्तमान में इसे बाहर कर दिया गया है। राष्ट्रीय टेक्स्टाइल कारपोरेशन दस उच्चतम लाभकारी उद्यमों में सम्मिलित नहीं था।

धातव्य है कि वर्तमान में 13 सार्वजनिक कंपनियों को नवरत्न तथा 11 कंपनियों को महारत्न की श्रेणी में शामिल किया गया है। इन 11 महारत्न कंपनियों में भेल, बीपीसीएल, गेल, आईओसी, सीआईएल, एचपीसीएल, एनटीपीसी, पीजीसी आईएल, सेल, ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड तथा पॉवर फाइनेंस कारपोरेशन शामिल हैं।

5. राष्ट्रीय नवीनीकरण फण्ड के गठन का उद्देश्य था—

- (a) सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों की पेंशन की व्यवस्था करना।
- (b) सामाजिक सुरक्षा।
- (c) उद्योगों की पुनःसंरचना और आधुनिकीकरण।
- (d) प्रामाण पुनर्निर्माण।

उत्तर-(b) UPPSC AE- 2008

UPPCS (Mains) Spl. G.S. IInd 2008

व्याख्या— नवीन औद्योगिक नीति 1991 के द्वारा राष्ट्रीय नवीनीकरण फण्ड की स्थापना की गई। जबकि इसकी स्थापना वर्ष 1992 में की गई। इस कोष का मुख्य उद्देश्य ऐसे श्रमिकों को सामाजिक सुक्षमा प्रदान करना है, जो कि प्रौद्योगिकी उन्नयन व आधुनिकीकरण के कारण प्रभावित हुए हैं।

6. भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई—

- | | |
|----------|----------|
| (a) 1989 | (b) 1990 |
| (c) 1991 | (d) 1992 |

उत्तर-(c) UPPCS (Pre) Economics Opt. 1997

व्याख्या— नई आर्थिक नीति की घोषणा 24 जुलाई, 1991, में तात्कालिक प्रधानमंत्री नरसिंह राव के द्वारा की गई। इस नई आर्थिक नीति के माध्यम से सरकार ने आर्थिक स्थिरीकरण एवं ढांचागत सुधार हेतु आर्थिक सुधार किये।

आर्थिक स्थिरीकरण मांग प्रबन्धन से है जबकि ढांचागत सुधार अर्थव्यवस्था के पूर्ति पक्ष के सुधार से है।

नई आर्थिक नीति (1991) में LPG सुधारों को प्रमुखता प्रदान की गयी। इसके तहत L-Libralisation (उदारीकरण), P-Privatisation (निजीकरण) तथा G-Globalisation (वैश्वीकरण) को अन्तर्निहित किया गया।

1. आर्थिक स्थिरीकरण—इसके अन्तर्गत तीन प्रकार के सुधार किये जाते हैं—

1. मुद्रास्फीति की नीची व स्थिर दर।
2. भुगतान संतुलन की समर्थ स्थिति।
3. राजकोषीय संतुलन।
2. ढांचा सुधार—इसके अन्तर्गत निम्न उपाय अपनाये जाते हैं—
 1. व्यापार तथा पूँजी प्रवाह सुधार।
 2. औद्योगिक नियन्त्रणों को समाप्त करना।
 3. सार्वजनिक उपक्रम सुधार और उनमें विनिवेश।
 4. वित्तीय क्षेत्र में सुधार।

7. स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति, जिस वर्ष घोषित की गई, वह था –

- | | |
|----------|----------|
| (a) 1947 | (b) 1948 |
| (c) 1951 | (d) 1956 |

उत्तर-(b)

**UPPCS Spl. (Pre) G.S. 2008
UP UDA/LDA (M) G.S., 2010**

व्याख्या— देश की औद्योगिक नीति वस्तुतः देश के औद्योगिक विकास के हर पहलू पर प्रकाश डालने वाला देश का आर्थिक संविधान है। 6 अप्रैल, 1948 को तत्कालीन उद्योग तथा वाणिज्य मंत्री डॉ. श्याम प्रसाद मुखर्जी ने स्वतंत्रता के बाद पहली औद्योगिक नीति का प्रस्ताव संसद में रखा। इस नीति में मिश्रित अर्थव्यवस्था की आर्थिक विचारधारा स्वीकार की गई जिसमें औद्योगिक विकास के लिए सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों पर बल दिया गया।

8. भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति अधिक उन्मुख है –

- (a) अर्थव्यवस्था के अधिक नियमन की ओर
- (b) वैश्वीकरण की ओर
- (c) लोकक्षेत्र को बढ़ाने की ओर
- (d) उपरोक्त सभी की ओर

उत्तर-(b)

UPPCS (Pre) G.S. Spl. 2004

व्याख्या— भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य उदारीकरण की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और तीव्र करना है ताकि भारतीय उद्योगों को वैश्वीकरण की ओर उन्मुख करके विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण किया जा सके।

9. भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा हुई—

- | | |
|-----------------|----------------|
| (a) अप्रैल 1948 | (b) मई 1948 |
| (c) जून 1948 | (d) मार्च 1948 |

उत्तर-(a)

UPPCS (Pre) Economics Opt. 1991

व्याख्या : भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल, 1948 को तत्कालीन केन्द्रीय उद्योग मंत्री डॉ श्याम प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। इस नीति के द्वारा ही देश में मिश्रित (निजी एवं सार्वजनिक) एवं नियंत्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई। इसमें उद्योगों को चार श्रेणियों में बांटा गया।

समाजवादी ढंग से समाज की स्थापना के उद्देश्य से दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा 30 April, 1956 को की गई। इसमें उद्योगों को तीन वर्गों में बाटा गया।

Dec, 1977 में जनता सरकार ने औद्योगिक नीति, 1977 की घोषणा की (उद्योग मंत्री जार्ज फर्नार्डिस)। इसमें लघु एवं कुटीर उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया गया।

July, 1980 में कांग्रेस सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक नीति, 1980 में सार्वजनिक उद्योगों के कुशलतम प्रबन्ध पर बल दिया गया।

24 July 1991 को औद्योगिक नीति की घोषणा प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने की। इसमें मुख्यतया औद्योगिक लाइसेंसिंग, MRTP Act, सार्वजनिक क्षेत्र, विदेशी निवेश तथा विदेशी प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में नीतिगत नियर्यों की घोषणा की गई।

10. निम्नलिखित में से कौन-सा 'प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना' के अन्तर्गत लक्षित समूह है?

- (a) डेयरी किसान
- (b) सीमान्त किसान
- (c) फुटपाथ विक्रेता
- (d) भूमिहीन कृषि श्रमिक

UPPCS (Pre) 2022

Ans. (c) : प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है जो लॉकडॉउन में ढील देने के पश्चात् पथ विक्रेताओं को अपनी आजीविका और रोजगार दोबारा शुरू करने के लिए किफायती दर पर कार्यशील पूँजीगत क्रहन प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगी।

इस योजना के अन्तर्गत लक्षित समूहों में, शहरों में फेरी लगाने वाले पथ विक्रेता, जिनमें शहरी इलाकों के आस-पास एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आए विक्रेता भी शामिल हैं जो 24 मार्च, 2020 या उससे पहले से बैंडिंग कर रहे थे। इस योजना में फुटपाथ विक्रेताओं को 10,000 रुपये तक की प्रारंभिक कार्यशील पूँजीगत क्रहन की सुविधा प्राप्त होगी। आर्थिक मामलों की मत्रियंडलीय समिति ने पीएम-स्वनिधि को मार्च, 2022 से आगे बढ़ाकर दिसंबर, 2024 तक जारी रखने को मंजूरी प्रदान की है।

11. देश का जी.डी.पी. के घटक हैं प्राथमिक, द्वितीय (सेकेन्डरी), तृतीय (ट्रिशियरी) और विदेशी क्षेत्र के उत्पाद। निम्न मद्दों में से उसे/उन्हें चिह्नित करिये जो द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं हैं—

- (a) निर्माण-उद्यम (मैन्युफैक्चरिंग)
- (b) निर्माण (कन्स्ट्रक्शन)
- (c) खनन
- (d) उपर्युक्त सभी

उत्तर-(c)

UPPSC AE-2007 II

व्याख्या— द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की विनिर्मित वस्तुओं के उत्पादन का लेखांकन किया जाता है। जैसे—

1. निर्माण, जहाँ किसी स्थायी परिस्थिति का निर्माण किया जाए जैसे— भवन।
2. विनिर्माण जहाँ किसी वस्तु का उत्पादन हो जैसे—कपड़ा ब्रेड आदि।
3. विद्युत गैस जल आपूर्ति से सम्बन्धित कार्य।

जबकि खाने एवं उत्खनन, कृषि, वानिकी, मत्त्य (मछली पकड़ना) प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।

12. उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है—

- | | |
|----------------|---------------|
| (a) कानपुर में | (b) लखनऊ में |
| (c) आगरा में | (d) नोयडा में |

उत्तर-(a)

UPPCS (Mains) G.S. Ist 2013

व्याख्या— उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय कानपुर में है। यह उत्तर प्रदेश सरकार का औद्योगिक एवं मूल अवसंरचना विकास की प्रगति के लिए कार्यरत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।

13. भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का अभिप्राय है :

- (a) किसी उद्योग में सरकार का 60 प्रतिशत से अधिक अंश
- (b) एक उद्यम जो कि संयुक्त रूप से निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र
- (c) दोनों सार्वजनिक और सरकारी क्षेत्रों द्वारा उत्पादित की गई कोई वस्तु
- (d) दोनों सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों द्वारा उत्पादित की गई कोई वस्तु

उत्तर-(b)

UPPCS (Pre) Economics Opt. 1996

व्याख्या— भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र से अभिप्राय यह है कि एक ऐसा उद्यम जो कि संयुक्त रूप से निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में है।

14. बी.आई.एफ.आर. (BIFR) सम्बन्धित है—

- (a) रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से
- (b) स्टाक एक्सचेंज की क्रियाओं के नियंत्रण से
- (c) खाद्य नियंत्रण से
- (d) विदेशी व्यापार नियंत्रण से

उत्तर-(a)

UPPCS (Pre) G.S. Spl. 2004

UPPCS (Mains) G.S. Ist 2002

व्याख्या—रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण के लिए जनवरी 1987 में एक सार्वजनिक संस्था औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (BIFR) की स्थापना की गई। BIFR की स्थापना टी. तिवारी समिति के सिफारिशों के आधार पर हुआ था।

15. भारत में 'सनराइज उद्योग' से क्या तात्पर्य है?

- (a) इलेक्ट्रॉनिक उद्योग
- (b) भारी उद्योग
- (c) कृषि-नियांत उद्योग
- (d) वस्त्र एवं परिधान उद्योग

उत्तर-(a) UPPCS ACF (Mains)-2017

व्याख्या— सनराइज उद्योग भारत में उभरते हुए उद्योगों को कहा जाता है इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा तथा ज्ञान से सम्बंधित उद्योग शामिल हैं।

16. नवरत्न का तात्पर्य है—

- (a) वे नौ बूटियां जिन से हर्बल फ्यूएल बनता है
- (b) नार्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नौ राज्य
- (c) सार्वजनिक क्षेत्र के वे नौ उद्योग जिन्हें पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई है
- (d) साप्टवेयर इक्विपमेंट के नौ घटक

उत्तर-(c) UPPCS BEO Re Exam- 2006

व्याख्या— नवरत्न का तात्पर्य सार्वजनिक क्षेत्र के वे उद्यम जिन्हें पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गयी है। ये कम्पनियाँ एक हजार करोड़ रुपये तक का निवेश स्वविवेक से कर सकती हैं। वर्तमान में वित्त मंत्रालय (फरवरी 2022) के आँकड़ों के अनुसार भारत में 11 महारत्न, 13 नवरत्न तथा 74 मिनी रत्न कम्पनियाँ हैं।

17. निम्न में से किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को चार 'नवरत्न' कम्पनियों को दिया गया 'महारत्न' का दर्जा नहीं प्राप्त हुआ?

- (a) सेल (SAIL)
- (b) बी.ई.एल.
- (c) ओ.एन.जी.सी.
- (d) एन.टी.पी.सी.

उत्तर-(b) UP RO/ARO (Pre) G.S., 2013

व्याख्या—प्रश्न काल के दौरान दिए गए विकल्पों में बी.ई.एल. (भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड) नवरत्न कम्पनी थी, जबकि शेष तीनों कम्पनियों को महारत्न का दर्जा दिया जा चुका था। वर्तमान में भी बी.ई.एल. (भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड) एक नवरत्न कम्पनी है।

लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी ताजा आँकड़ों (फरवरी 2022) के अनुसार, भारत में 11 महारत्न, 13 नवरत्न तथा 74 मिनीरत्न कम्पनियाँ हैं। 11 महारत्न कम्पनियाँ इस प्रकार हैं:

1. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL)
2. भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (BPCL)
3. कोल इंडिया लिमिटेड (CIL)
4. गेल इंडिया लिमिटेड (GAIL)
5. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (HPCL)
6. इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (IOCL)
7. नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (NTPC)
8. ऑयल एण्ड नैचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ONGC)
9. पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL)
10. स्टील अर्थोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL)
11. पॉवर फाइनेंस कार्पोरेशन (PFC)

18. "नवरत्न" का विचार सम्बन्धित है—

- (a) तकनीकी जनशक्ति के चयनित वर्ग
- (b) चयनित नियांतोन्मुखी इकाइयाँ

(c) चयनित खाद्य-प्रसंस्करण उद्योग

(d) सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम

उत्तर-(d)

UPPCS (Pre) G.S. 2008

व्याख्या— 1997-98 के केन्द्रीय बजट में अच्छा निष्पादन करने वाले 9 सार्वजनिक उपक्रमों को चुना गया और उन्हें नवरत्नों की संज्ञा दी गयी। उस समय मूलतः 9 कम्पनियों को यह दर्जा प्रदान किया गया था। नवरत्न का दर्जा उन कम्पनियों को प्रदान किया जाता है। जो वैश्विक कम्पनी के रूप में देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो जाने से इन कम्पनियों को ज्यादा प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता मिलती है। यह कम्पनियाँ सरकार की अनुमति के बाहर देश या विदेश में संयुक्त उद्यम लगा सकती हैं और उनमें अपनी नेटवर्क के 15 प्रतिशत तक निवेश कर सकती हैं। इतना ही नहीं, इन कम्पनियों के निवेशक बोर्ड को अधिग्रहण और विलय सम्बन्धी नियंत्रण लेने का अधिकार होता है।

19. निम्नलिखित में कौन एक जैसा नहीं है?

- (a) SAIL
- (b) BHEL
- (c) ONGC
- (d) ESSAR OIL

उत्तर-(d) UPPCS (Pre.) G.S. 1997

व्याख्या— SAIL, BHEL तथा ONGC सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हैं, जबकि ESSAR OIL एक निजी क्षेत्र का उद्यम है। वर्तमान में SAIL, BHEL तथा ONGC यारह महारत्न कम्पनियों में से हैं।

20. 'नवरत्न' में सम्मिलित सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है

- (a) सेल (SAIL)
- (b) गेल (GAIL)
- (c) एम.टी.एन.एल. (MTNL)
- (d) उपरोक्त सभी

उत्तर-(c) UPPCS (Mains) G.S. Ist Paper 2012

व्याख्या— प्रश्न काल के दौरान, सेल (SAIL) एक महारत्न दर्जा प्राप्त कम्पनी थी। जबकि GAIL और MTNL नवरत्न दर्जा प्राप्त कम्पनियाँ थी। अतः प्रश्न गलत था।

वर्तमान में दिए गए विकल्पों में SAIL एवं GAIL महारत्न कम्पनियाँ हैं, जबकि MTNL एक नवरत्न कम्पनी है। GAIL को 2013 में महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ था।

21. निम्नलिखित में से कौन 'नवरत्नों' में नहीं है?

- (a) एन.टी.पी.सी.
- (b) स्टील ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया
- (c) तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम
- (d) कोल इण्डिया लिमिटेड

उत्तर-(*) UPPCS ACF (Mains)-2017

व्याख्या— प्रश्न त्रुटिपूर्ण है क्योंकि प्रश्न में उल्लेखित सभी उपक्रम महारत्न कम्पनियाँ हैं।

22. भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ ₹ तक तथा कोरोबार 5 करोड़ ₹ तक है, उन्हें जाना जाता है—

- (a) छोटे उद्यम
- (b) लघु उद्यम
- (c) सूक्ष्म उद्यम
- (d) मध्यम उद्यम

UPPSC RO/ARO (Pre) 2021

Ans. (c) : भारत में एक करोड़ रुपये तक के विनियोग तथा 5 करोड़ रुपये तक के कारोबार करने वाले उद्यमों को सूक्ष्म उद्यम के रूप में परिभाषित किया गया है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का वर्गीकरण निम्नलिखित है-

उद्यम का प्रकार	विनियोग	वार्षिक टर्न ओवर
सूक्ष्म	1 करोड़ तक	5 करोड़ तक
लघु	1 करोड़ से 10 करोड़ तक	5 करोड़ से 50 करोड़ तक
मध्यम	10 करोड़ से 50 करोड़ तक	50 करोड़ से 250 करोड़ तक

23. एम. एस. एम. ई. अधिनियम के अन्तर्गत एक लघु उद्यम है, जिसका वार्षिक कारोबार होगा-

- (a) ₹ 1 करोड़ से 50 करोड़
- (b) ₹ 5 करोड़ से 50 करोड़
- (c) ₹ 5 करोड़ से 75 करोड़
- (d) ₹ 10 करोड़ से 100 करोड़

उत्तर-(c) UPPCS ACF (Mains)-2017

व्याख्या-उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

24. सूची-(I) को सूची-(II) से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।

सूची-(I)	सूची-(II)
(फल)	(प्रजाति)
A. अमरुद	1. पूसा ड्वाफ
B. आंवला	2. हरीछाल
C. पपीता	3. कृष्णा
D. केला	4. चिन्निदार

कूट:

A	B	C	D
(a) 2	3	1	4
(b) 3	4	1	2
(c) 4	3	1	2
(d) 4	3	2	1

उत्तर-(c) UP PSC ACF/RFO (Mains) 2020 Paper I

व्याख्या-प्रजाति एवं फलों का सही सुमेलन निम्नलिखित है-

प्रजाति	-	फल
हरिछाल	-	केला
कृष्णा	-	आंवला
चिन्निदार	-	अमरुद
पूसा ड्वाफ	-	पपीता

25. सूची-(I) को सूची-(II) से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।

सूची-(I)	सूची-(II)
(फसल)	(प्रजाति)
A. धान	1. रत्ना
B. सरसों	2. नीलम
C. अलसी	3. रचना
D. मटर	4. वस्त्रण

कूट:

A	B	C	D
(a) 3	4	1	2
(b) 1	4	2	3
(c) 4	3	2	1
(d) 1	2	3	4

उत्तर-(b) UP PSC ACF/RFO (Mains) 2020 Paper I

व्याख्या-प्रमुख फसलों एवं उनकी प्रमुख प्रजातियों के नाम निम्नलिखित है-

फसल प्रजातियाँ

- धान - रत्ना, जया, पद्मा, अमन, बोरो, पूसा सुगंधा आदि
- गेहूँ - कल्याण सोना, सोनालिका आदि
- अलसी - हिमानी, मुक्ता, नीलम, जवाहर-17 आदि
- मटर - रचना, अपर्णा, सपना, उत्तर, पूसा प्रगति आदि
- मंसूर - मलिका, प्रिया, गरिमा, पूसा वैभव आदि
- सरसों - गिरिराज, पीताम्बरी, वरुण, दिव्या-33 आदि

26. निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अंशदान नहीं देता है?

- (a) पशुपालन
- (b) कुटीर उद्योग
- (c) निजी धन उधार देने का प्रचलन
- (d) अच्छे उपकरणों की उपलब्धता

उत्तर-(c) UP Lower (Pre.) G.S. 2013

व्याख्या – निजी धन उधार देने का प्रचलन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं देता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कुटीर उद्योग, पशुपालन और अच्छे यंत्र मुख्य रूप से योगदान देते हैं।

27. 2011 में सूक्ष्म एवं वित्त संस्थाएँ (माइक्रो-फाइनेंस इंस्टीट्यूशन) निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर स्थापित किए गए?

- (a) मालेगाम समिति
- (b) गोइपोरिया समिति
- (c) रंगराजन समिति
- (d) बैंकिंग रिफॉर्म्स समिति

उत्तर – (a) UP RO/ARO (Pre) G.S., 2014

व्याख्या – 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएँ (माइक्रो-फाइनेंस इंस्टीट्यूशन) मालेगाम समिति की सिफारिश पर स्थापित किये गये थे। बैंकों में खराब ऋण, धोखाधड़ियों के बढ़ते मामले की निगरानी हेतु भी मालेगाम समिति का गठन किया गया था।

28. आबिद हुसैन समिति का संबंध था –

- (a) निर्यात सम्बद्धन से
- (b) लघु एवं मध्यम उद्योग से
- (c) कृषि विकास से
- (d) ऊर्जा क्षेत्र सुधार से

उत्तर – (b) UPPCS (Mains) G.S.-IInd 2006

व्याख्या – लघु उद्योगों की समस्याओं का अध्ययन करके उनके विकास हेतु सुझाव देने के लिए उद्योग मंत्रालय द्वारा डॉ. आबिद हुसैन की अध्यक्षता में 1995 में समिति गठित की गयी थी।

29. भारत में प्रथम उद्योग जिस का विकास हुआ, वह है–

- (a) कुटीर उद्योग
- (b) सीमेन्ट उद्योग
- (c) आयरन और स्टील उद्योग
- (d) अभियान्त्रिकी उद्योग

उत्तर-(a) UP Lower (Pre.) G.S. 2008

व्याख्या—भारत में सर्वप्रथम कुटीर उद्योग का विकास हुआ। आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर उद्योग का योगदान 43% है। इसमें लगभग 35% जनसंख्या लगी हुई है। कुटीर उद्योग उसे कहा जाता है जो अंशतः पारिवारिक सदस्यों द्वारा आंशिक अथवा पूर्ण कालिक कार्य के रूप में चलाया जाता है। कुटीर उद्योग कहलाता है। ऐसे उद्योगों में हस्तक्रिया की प्रधानता होती है। भारत का सबसे बड़ा कुटीर उद्योग हथकरघा उद्योग है उसके बाद खाड़सारी उद्योग आता है।

30. भारत जैसे विकासशील देश के लिए लघुस्तरीय व कुटीर उद्योगों को मुख्यतः इसलिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि वे—

- सम्पत्ति का वितरण समान करते हैं
- अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं
- कम लागत पर उत्पादन करते हैं
- कम पूँजी विनियोग की अपेक्षा करते हैं

उत्तर—(b) UPPCS (Mains) G.S. Ist 2004

व्याख्या—भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले विकासशील देश के लिए लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ऐसे उद्योगों से रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न होंगे जिससे बेरोजगारी की विकट समस्या का कुछ हद तक समाधान संभव होगा। इन उद्योगों की स्थापना के लिए कम पूँजी की जरूरत होती है जो कि भारत जैसे पिछड़े देश के लिए अनुकूल है।

31. वर्ष 2006 में पारित अधिनियम के अनुसार सूक्ष्म उपकरणों के लिए निवेश की सीमा है—

- | | |
|---------------|-------------------------------|
| (a) रु 10 लाख | (b) रु. 5 लाख |
| (c) रु. 2 लाख | (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं |

उत्तर—(a) UPPCS (Mains) G.S. IInd Paper 2011

व्याख्या—सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के पश्चात् लघु उद्योग को अब अधिक व्यापक रूप में छोटे, लघु एवं मझोले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में एम.एस.एम.ई. की नई परिभाषा के अनुसार, सूक्ष्म उद्यम वह है जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपस्कर में एक करोड़ रुपये से अधिक का निवेश नहीं होता तथा उसका कारोबार 5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होता है यह सीमा लघु उद्योग के लिए 10 करोड़ से कम का निवेश तथा 50 करोड़ से कम का कारोबार तथा मध्यम उद्योग के लिए 50 करोड़ से कम का निवेश तथा 250 करोड़ से कम का कारोबार है।

32. निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है—

- पूँजी का अभाव
- विपणन जानकारी का अभाव
- कच्चे माल का अभाव
- उपरोक्त सभी

उत्तर—(d) UPPCS (Pre.) G.S. 1991

व्याख्या—भारत में लघु उद्योगों को कुटीर उद्योगों के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण में कुटीर उद्योगों को लघु उद्योगों से भिन्न श्रेणी में रखा जाता है। लघु उद्योगों की प्रमुख समस्याएँ इस प्रकार हैं—

- (1) वित्त तथा साख
- (2) कच्चे माल की अनुपलब्धि
- (3) मशीनें तथा दूसरे उपकरण
- (4) क्षमता का अल्प प्रयोग
- (5) विपणन की समस्याएँ
- (6) पूँजी की कमी।

लघु उद्योगों की उपरोक्त समस्याओं के अतिरिक्त अन्य समस्याएँ हैं—प्रबंधकीय क्षमता का अभाव, सस्ती विद्युत का उपलब्ध न होना, स्थानीय करों का भार तथा बड़े उद्योगों के साथ प्रतियोगिता न कर पाना आदि।

33. निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु उद्योगों (SSIs) की समस्या नहीं है?

- | | |
|---------------|--------------------------|
| (a) वित्त | (b) विपणन |
| (c) कच्चे माल | (d) हड्डताल एवं तालाबंदी |

उत्तर—(d) UPPCS (Pre) G.S. 2008

व्याख्या—हड्डताल एवं तालाबंदी जो कि श्रमिक संघों द्वारा अपनी मांगों की पूर्ति हेतु प्रबंधन पर दबाव बनाने हेतु किया जाता है, लघु उद्योगों की समस्या नहीं है।

34. निम्न में से किसके लिए 'उद्यमी' हेल्पलाइन स्थापित की गई है?

- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपकरणों के लिए
- बड़ी पूँजी वाले उद्योगों के लिए
- महिला उद्यमियों के लिए
- कृषि में प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने वाले कृषकों के लिए

उत्तर—(a)

व्याख्या—20 अगस्त, 2010 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपकरणों के लिए 'उद्यमी' हेल्पलाइन का शुभारम्भ किया था।

35. निम्नलिखित में से किस एक समिति ने उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की सिफारिश की?

- | | |
|----------------------|----------------------|
| (a) आबिद हुसैन समिति | (b) नरसिंहन समिति |
| (c) नायक समिति | (d) राकेश मोहन समिति |

उत्तर—(a) UPPCS (Pre) G.S. 2006

व्याख्या—लघु उद्योगों की समस्याओं का अध्ययन करके उनके विकास हेतु सुझाव देने को उद्योग मन्त्रालय द्वारा गठित डॉ. आबिद हुसैन समिति की सिफारिशों को 27 जनवरी 1997 को सार्वजनिक रूप से घोषित कर दिया गया था। समिति का गठन दिसम्बर 1995 में किया गया। समिति की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित थीं—

- लघु उद्योगों में निवेश सीमा को मौजूदा 60/75 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये किया जाय।
- लघुतर इकाइयों (Tiny Units) में निवेश सीमा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रु. की जाय।
- लघु उद्योगों के लिए उत्पादों के आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त किया जाय (जून 2005 तक 497 उत्पादों का उत्पादन लघु उद्योगों के लिए आक्षित था) आदि।

नरसिंहन समिति वित्तीय सुधार से सम्बन्धित है तथा नायक समिति लघु उद्योग क्षेत्र की वित्त एवं रुग्णता सम्बन्धी समस्याओं के मूल्यांकन के लिए गठित की गई थी। वर्ष 2015 से लघु उद्योगों के लिए आरक्षित अंतिम 20 उत्पादों को प्राप्त आरक्षण समाप्त कर दिया गया।

36. भारत के 'विनिवेश आयोग' का प्रथम अध्यक्ष कौन था?

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| (a) जी.वी. रामकृष्ण | (b) सी. रंगराजन |
| (c) अरुण जेटली | (d) मोन्टेक सिंह अहलुवालिया |

उत्तर—(a) UPPCS (Mains) Spl. G.S. IInd, 2004

व्याख्या—भारत में प्रथम विनिवेश आयोग का गठन वर्ष 1996 में जी.वी. रामकृष्ण की अध्यक्षता में किया गया। अगस्त 1999 तक इस कमेटी ने 58 सार्वजनिक उद्योगों से सम्बन्धित सिफारिशें दी। आयोग की सिफारिशों के आधार पर विनिवेश हेतु 16 मार्च, 1999 को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को दो भागों सामरिक और गैर-सामरिक में बाँटा गया।

नोट : भारतीय संदर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी अंशधारिता नियन्त्रण को निजी हाथों में बेचे जाने की प्रक्रिया विनिवेश कहलाता है। भारत में विनिवेश की प्रक्रिया का आरम्भ वर्ष 1991–92 रहा है।

37. निम्न में से कौन-सा युग्म सुमेलित नहीं है?

- | | |
|-------------------------|-----------|
| (a) तेल शोधनशाला | — मथुरा |
| (b) उर्वरक संयंत्र | — लखनऊ |
| (c) कालीन उद्योग | — भद्रोही |
| (d) एल्यूमीनियम उत्पादन | — सोनभद्र |

उत्तर-(b) UPPCS (Pre) Ist Paper GS, 2014

व्याख्या— उत्तर प्रदेश में उर्वरक संयंत्र गोरखपुर, प्रयागराज (फूलपुर), कानपुर, बरेली में स्थित है, लखनऊ में नहीं। जबकि तेल शोधनशाला मथुरा में, कालीन उद्योग भद्रोही में और एल्यूमीनियम संयंत्र सोनभद्र में स्थित है।

38. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में सर्वाधिक भार किस क्षेत्र का है?

- | | |
|-----------|-----------------------|
| (a) खनन | (b) उत्पादन |
| (c) बिजली | (d) प्राथमिक वस्तुयें |

UPPSC ACF/RFO (Mains) Paper-II 2021

Ans. (c) : औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में सर्वाधिक भार बिजली क्षेत्र का है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक एक संकेतक है जो एक निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन को मापता है। प्रमुख क्षेत्र के उद्योग उनके भार के घटते क्रम में- रिफाइनरी उत्पाद > बिजली > स्टील > कोयला > कच्चा तेल > प्राकृतिक गैस > सीमेंट > उर्वरक। इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुर्भूत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है।

39. राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी

- | |
|---------------------------------------|
| (a) यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से |
| (b) रूस के सहयोग से |
| (c) संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से |
| (d) जर्मनी के सहयोग से |

उत्तर-(d) UPPCS (Mains) G.S. Ist 2012

व्याख्या— राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से वर्ष 1959 में हुई थी। ओडिशा राज्य में स्थित यह भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र है।

40. निम्नलिखित में विपणन संस्था कौन सी है?

- | | |
|--------------------|----------------------|
| (a) सेबी (SEBI) | (b) सेल (SAIL) |
| (c) सिड्बी (SIDBI) | (d) नाबार्ड (NABARD) |

उत्तर-(b) UPPCS (Mains) G.S. Ist 2002

व्याख्या— दिए गए विकल्पों में सेल (SAIL) विपणन संस्था है। इसका पूरा नाम स्टील अर्थोस्टी ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना 24 जनवरी, 1973 ई. में सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों का प्रबंधन एवं स्वामित्व सौंपने के लिए किया गया। यह सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों से उत्पादित इस्पात का विपणन भी देखती है।

41. नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही कथन/कथनों का चयन कीजिये:

1. नये पी.एस.यू. (सार्वजनिक उपक्रमों) की स्थापना आर्थिक सुधारों की भावना के विपरीत है।
2. विनिवेश की प्रक्रिया विराष्ट्रीयकरण की ओर नहीं ले जायेगी।

कूट:

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| (a) केवल 1 | (b) केवल 1 |
| (c) 1 और 2 दोनों में | (d) उपरोक्त में से कोई नहीं |

उत्तर-(a) UP PSC ACF/RFO (Mains) 2018 Paper II

व्याख्या—आर्थिक सुधार एक वृहद संकल्पना है। प्रायः इसका अर्थ अल्पतम सरकारी नियंत्रण, अल्पतम सरकारी निषेध, निजी कंपनियों की अधिक भागीदारी, करों का अल्पतम दर आदि के संदर्भ में लगाया जाता है, अतः नए सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना इसके विपरीत माना जाता है, जबकि सरकारी या सार्वजनिक उपक्रमों में सरकार की हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया विनिवेश कहलाती है। विनिवेश की प्रक्रिया आर्थिक सुधारों के अनुकूल है। इससे प्राप्त होने वाली रकम का इस्तेमाल सरकार विकास योजनाओं में खर्च करती है। परंतु विनिवेश की प्रक्रिया विराष्ट्रीकरण को बढ़ावा देती है, यद्यपि की विनिवेश प्रक्रिया में सरकार अपना कुछ हिस्सा निकालती है, परंतु उसकी मिल्कियत बनी रहती है।

42. भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया—

- | | |
|--------------|--------------|
| (a) 2001 में | (b) 2002 में |
| (c) 2003 में | (d) 2004 में |
- उत्तर-(b) UPPCS (Mains) G.S. Ist 2004

व्याख्या—भारत में विजय राघवन समिति की सिफारिश पर 1969 के एकाधिकार तथा प्रतिबंधित व्यापार अधिनियम (MRTP) के स्थान पर सन् 2002 में 10 सदस्यीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया जो 2003 में प्रभावी हुआ। इस आयोग का प्रमुख कार्य अनुचित प्रतिस्पर्धा तथा एकाधिकार को नियंत्रित करना और कम्पनियों के विलय तथा एकाधिकार को नियंत्रित करना और कम्पनियों के विलय तथा अधिग्रहण पर निर्गानी रखना है।

43. भारत में विलय एवं अधिग्रह, के सन्दर्भ में कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- I. सभी विलय एवं अधिग्रहण, जिनमें एफ.डी.आई.समिलित हैं, में एन.सी.एल.टी. के अनुमोदन की जरूरत होती।
- II. निवेशकर्ताओं को 23 दस्तावेज जमा करने होते हैं।
- III. इन 23 दस्तावेजों में से 20 दस्तावेज अनिवार्य हैं।

कूट:

- | | |
|---------------|-------------------|
| (a) I तथा II | (b) II तथा III |
| (c) I तथा III | (d) I, II तथा III |

UP PSC ACF/RFO (Mains) 2020 Paper II

Ans. (a) : राष्ट्रीय कम्पनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) का गठन कम्पनी अधिनियम 2013 के तहत 2016 में किया गया जिसने कम्पनी अधिनियम 1956 का स्थान लिया है। भारत में विलय एवं अधिग्रहण, जिसमें एफ.डी.आई. समिलित सभी के लिए NCLT के अनुमोदन की आवश्यता होती है। साथ ही निवेशकर्ता को 23 दस्तावेज जमा करने होते हैं, जिसमें से 9 अनिवार्य होते हैं। अतः कथन III गलत है।

44. वह कौन-सा वित्तीय वर्ष है, जिससे सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरम्भ हुआ?

- | | |
|-------------|-------------|
| (a) 1990-91 | (b) 1991-92 |
| (c) 1992-93 | (d) 1993-94 |

उत्तर-(b) UPPCS Spl, (Pre) G.S. 2008

व्याख्या— विनिवेश या सार्वजनिक उद्यमों में सरकार के अपने स्वामित्व में कभी लाने की प्रक्रिया का प्रारम्भ भारत में डॉ. मनमोहन सिंह ने किया जबकि वित्तमंत्री के रूप में पहली बार 1991-92 बजट में विनिवेश का प्रयोग किया। जब वित्तमंत्री ने 1991-92 में 2500 करोड़ रुपये के विनिवेश की बात कही और उस बजट वर्ष में 3038 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई। 1992 में सार्वजनिक उद्यमों के विनिवेश के लिए सी. रंगराजन कमेटी गठित की गई जिसने अपनी रिपोर्ट 1993 में दी।